राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक समाचार पत्र

RNI NO - UPHIN/2022/86937

जौनपुर से प्रकाशित

देश की उपासना

देश के विकास में समर्पित समाज के सभी वर्गों के लिए

DKU LIVE

सब पर नज़र, सबकी खबर

वर्ष – 04 | अंक – 38 | जौनपुर | शनिवार, 20 सितम्बर 2025 | सान्ध्य दैनिक (संस्करण) | पेज – 4 | मूल्य – 2 रूपये

संक्षिप्त खबरें

बॉम्बे हाईकोर्ट को एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी

मुंबई, (एजेंसी)। बॉम्बे हाईकोर्ट को आज यानी शुक्रवार सुबह एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी मिली, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया। हाईकोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर एक धमकी भरा ईमेल मिलने के तुरंत बाद, मुंबई पुलिस की टीम और बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचा और पूरे परिसर की सघन तलाशी ली। हालांकि, घंटों की जांच के बाद कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला, जिसके बाद अधिकारियों ने राहत की सांस ली। मुंबई पुलिस ने एक बयान में जानकारी दी कि धमकी मिलने के बाद मानक प्रक्रिया के तहत उच्च न्यायालय परिसर की पूरी तरह से जांच की गई, लेकिन कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है। गौरतलब है कि ठीक एक हफ्ते पहले भी ऐसी ही धमकी दी गई थी। बता दें कि बीते शुक्रवार, 12 सितंबर को भी हाईकोर्ट को इसी तरह का धमकी भरा ईमेल मिला था। उस समय मामले की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट प्रशासन ने सभी जजों, वकीलों, कर्मचारियों और अन्य लोगों को तुरंत कोर्ट परिसर खाली करने का आदेश दिया था। उस दिन भी बम निरोधक दस्ते ने पूरे परिसर की जांच की थी, लेकिन वह धमकी भी झूठी साबित हुई थी। सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार, हाल के दिनों में देश के महत्वपूर्ण संस्थानों को इस तरह की फर्जी धमकियां देने का चलन बढ़ा है, जिसका मकसद केवल दहशत फैलाना होता है। पुलिस ईमेल भेजने वाले के आईपी एड्रेस का पता लगाकर आरोपी तक पहुंचने की कोशिश कर रही है।

मिजोरम में असम राइफल्स की बड़ी कार्रवाई

आइजोल, (एजेंसी)। भारत–म्यांमार सीमा पर नशीली दवाओं की तस्करी के खिलाफ भारतीय सेना की कार्रवाई जारी है। स्पीयर कोर के तहत आने वाली असम राइफल्स की यूनिट ने 34 किलो से अधिक मेथामफेटामाइन टैबलेट (ड्रग्स) को जब्त किया है, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 102.65 करोड़ रुपए है। स्पीयर कोर इंडियन आर्मी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शुक्रवार को एक पोस्ट शेयर कर इस कार्रवाई की जानकारी दी। स्पीयर कोर इंडियन आर्मी के अनुसार, असम राइफल्स ने यह कार्रवाई मिजोरम के चम्फाई जिले के जोटे इलाके में की है। स्पीयर कोर इंडियन आर्मी ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, स्पीयर कोर के तहत असम राइफल्स ने 18 सितंबर 2025 को मिजोरम के चम्फाई (जोटे) में 102.65 करोड़ (लगभग) मूल्य की 34.218 किलोग्राम मेथामफेटामाइन टैबलेट जब्त की। आगे की जांच के लिए प्रतिबंधित सामग्री को आबकारी और नारकोटिक्स विभाग चम्फाई को सौंप दिया गया है। विशिष्ट खुफिया जानकारी के आधार पर असम राइफल्स की टीम ने संदिग्ध व्यक्ति को रोका, जो कंसाइनमेंट लेकर जा रहा था। चुनौती पर वह सामान छोड़कर जंगल में भाग गया।

गुजरात, 4500 करोड़ से बन रहे नेशनल मरीन हेरिटेज कॉम्प्लेक्स का पीएम मोदी लेंगे जायजा

गांधीनगर, (एजेंसी)। पीएम नरेंद्र मोदी शनिवार को अपने गृह प्रदेश गुजरात जाएंगे। इस दौरे पर वह अहमदाबाद के लोथल में बन रहे नेशनल मरीन हेरिटेज कॉम्प्लेक्स (एनएमएचसी) की प्रगति का जायजा लेंगे और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी करेंगे। लोथल कभी सिंधु घाटी सभ्यता का अहम व्यापारिक केंद्र था। अब लोथल में देश की समुद्री विरासत को दिखाने के लिए भव्य कॉम्प्लेक्स बन रहा है। गुजरात के मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान के मुताबिक, एनएमएचसी पीएम मोदी के पंच प्रण में से एक प्राचीन धरोहरों के संरक्षण का प्रतीक है। इस परियोजना का मकसद विकास भी, विरासत भी यानी इतिहास, शिक्षा, शोध और मनोरंजन का मेल है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा कि लोथल में हेरिटेज संग्रहालय का निर्माण इसलिए किया जा रहा है, ताकि हर नागरिक अपने इतिहास को आसानी से समझ सकें। इसमें नई तकनीक का इस्तेमाल होगा, जिससे उस प्राचीन समय की भव्यता को फिर से दिखाया जा सके। 375 एकड़ में फैला है कॉम्प्लेक्स करीब 4,500 करोड़ रुपये की लागत से बन रहा यह कॉम्प्लेक्स 375 एकड़ में फैला है। इसमें दुनिया का सबसे ऊंचा लाइटहाउस म्यूजियम (77 मीटर), 14 गैलरी, तटीय राज्यों का पवेलियन, चार थीम पार्क और एक फ्लोटिंग रेस्टोरेंट होगा। साथ ही 100 कमरों वाला टेंट सिटी और रिसॉर्ट, ई–कार सुविधा और 500 इलेक्ट्रिक गाड़ियों की पार्किंग भी होगी। एनएमएचसी में रात का लाइट शो, लोथल की मिनी झलक और दुनिया की सबसे बड़ी अंडरवॉटर गैलरी पर्यटकों को खूब आकर्षित करेगी। इससे न सिर्फ सैलानियों की संख्या बढ़ेगी,।

युद्ध में जीत सामुहिक संकल्प का परिणाम : राजनाथ

नई दिल्ली, (एजेंसी)। देश की सुरक्षा केवल सीमा पर लड़े गए युद्ध से तय नहीं होती, बल्कि यह पूरे देश के लोगों के संकल्प और एकजुटता से तय होती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 1965 के युद्ध के दिग्गजों से बातचीत में यह बात कही। 1965 के भारत–पाकिस्तान युद्ध के जांबाजों के साथ बातचीत में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, ष्भारत अपने पड़ोसियों के साथ संबंधों के मामले में भाग्यशाली नहीं रहा है... लेकिन हमने इसे नियति नहीं माना है। हमने अपनी नियति स्वयं तय की है... इसका एक उदाहरण ऑपरेशन सिंदूर है। अपने संबोधन के दौरान रक्षा मंत्री ने देश के विकास में जवानों और किसानों की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में भी बात की। रक्षा मंत्री ने कहा कि हम पहलगाम की भयावह घटनाओं को नहीं भूले हैं और जब भी हम उन्हें याद करते हैं, हमारा दिल भारी हो जाता है और मन क्रोध से भर जाता है। वहां जो हुआ उसने हम सभी को झकझोर दिया। लेकिन वह घटना हमारे मनोबल को नहीं तोड़ पाई। राजनाथ

सिंह ने कहा, हमारे प्रधानमंत्री ने आतंकवादियों को ऐसा सबक सिखाने का संकल्प लिया जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। हमने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया और अपने दुश्मनों को दिखाया कि हमारा प्रतिरोध कितना मजबूत और शक्तिशाली है। हमारी पूरी टीम की ओर से दिखाए गए समन्वय और करिश्मे ने साबित कर दिया कि जीत अब कोई अपवाद नहीं है। जीत एक आदत बन गई है और हमें इस आदत को हमेशा बनाए रखना चाहिए। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कहते हैं, ष .. कोई भी युद्ध केवल युद्ध के मैदान में नहीं लड़ा जाता, बल्कि युद्ध में प्राप्त विजय पूरे राष्ट्र के सामूहिक संकल्प का परिणाम होती है। 1965 के उस कठिन समय में, जब चारों ओर अनिश्चितता और चुनौतियाँ थीं, देश ने लाल बहादुर शास्त्री के दृढ़ नेतृत्व में उन चुनौतियों का सामना किया। शास्त्री जी ने उस दौर में न केवल निर्णायक राजनीतिक नेतृत्व प्रदान किया, बल्कि पूरे देश का मनोबल भी ऊंचाइयों तक पहुंचाया।

मायावती 2.0 में कितनी मजबूत होगी बसपा, भाजपा–सपा का कितना खिसकेगा जनाधार

लखनऊ, (संवाददाता)। बहुजन समाज पार्टी यूपी की सियासत में एक बार फिर अपने लिए मजबूत भूमिका की तलाश में है। इसके लिए पार्टी नौ अक्टूबर को लखनऊ के कांशीराम स्मारक स्थल पर बड़ी जनसभा करने की तैयारी कर रही है। बसपा संस्थापक कांशीराम की पुण्यतिथि पर आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में लाखों लोगों के पहुंचने की संभावना है। यूपी की राजधानी में बड़ी रैली कर मायावती अपनी वापसी के

मजबूत संकेत देना चाहती हैं। इसे मायावती के द्वारा 2027 के यूपी चुनाव की शंखनाद भी माना जा रहा है। बड़ा प्रश्न यह है कि मायावती की ये कोशिशें कितनी सफल होंगी? बसपा के मजबूत होने से भाजपा के समीकरणों पर क्या असर पड़ेगा? अखिलेश यादव ने जिस पीडीए समीकरण के सहारे पिछले लोकसभा चुनाव में सफलता पाई है, उन समीकरणों में नई परिस्थितियों में क्या परिवर्तन आ सकता है? पिछले तीन लोकसभा चुनावों और तीन यूपी विधानसभा चुनावों में बसपा लगातार कमजोर होती गई है। उसके परंपरागत वोट बैंक का एक छोटा हिस्सा ही उसके साथ रह गया है। बसपा के खराब प्रदर्शन से निराश दलित और अति पिछड़े मतदाताओं ने धीरे–धीरे भाजपा और सपा की ओर रुख कर लिया है। इन समर्थकों में एक बड़ा वर्ग आज भी ऐसा है जो दिल से बसपा से जुड़ा हुआ है, लेकिन अपना वोट खराब न करने के कारण दूसरे दलों के साथ जुड़ गया है। यदि मायावती इस वर्ग के लोगों के बीच यह भरोसा पैदा करने में सफल हो जाती हैं कि वे पूरी मजबूती के साथ वापसी करने के लिए तैयार हैं तो पहली कोशिश में ही इस वर्ग का एक हिस्सा वापस उनके साथ जुड़ सकता है।

अब हर सैनिक बनेगा ड्रोन योद्धा हर कंधे पर होगा तकनीकी हथियार

नई दिल्ली, (एजेंसी)। भारतीय सेना ऑपरेशन सिंदूर से मिली सीख के हिसाब से खुद को तैयार करने में जुट गई है। सेना ने युद्ध स्तर पर ड्रोन और ड्रोन–रोधी प्रणालियों को ऑपरेशनल यूनिट्स में शामिल करना शुरू कर दिया है। सेना प्रमुख ने बृहस्पतिवार को अरुणाचल प्रदेश के लिकाबाली में ऐसी ही ड्रोन सुविधा का जायजा लिया। सेना ने पहले ही देहरादून स्थित सैन्य अकादमी, महू स्थित इन्फैंट्री स्कूल और चेन्नई स्थित अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी जैसी प्रशिक्षण अकादमियों में ड्रोन केंद्र स्थापित किए गए हैं। इसका उद्देश्य सेना के सभी अंगों के सैनिकों के लिए ड्रोन संचालन को एक मानक परिपाटी बनाना है। सेना के अधिकारियों ने बताया कि सेना का दृष्टिकोण ईगल इन द आर्म अवधारणा से प्रेरित है, यानी हर सैनिक के हाथ में बाज (ड्रोन) होना चाहिए। बंदूक की तरह ड्रोन चलाना आना चाहिए। सेना में ड्रोन का उपयोग युद्ध के अलावा निगरानी में, रसद पहुंचाने में और यहां तक कि घायल सैनिकों तक चिकित्सा सहायता पहुंचाने के लिए भी होगा। इस साल 26 जुलाई को द्रास में 26वें कारगिल विजय दिवस समारोह के दौरान सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने भी घोषणा की थी कि हर इन्फैंट्री बटालियन में एक ड्रोन प्लाटून होगी। आर्टिलरी रेजिमेंट को ड्रोन रोधी प्रणालियों और लॉइटरिंग म्युनिशन (युद्धक ड्रोन) से लैस किया जाएगा। सेना प्रमुख ने कहा था कि भविष्य में एक आधुनिक सेना बनने की दिशा में तेजी से कार्य हो रहा है और आने वाले दिनों में सेना की मारक क्षमता पहले से कई गुना बढ़ जाएगी।

राहुल गांधी के वोट-चोरी के आरोप पर अजित पवार का पलटवार

नागपुर, (एजेंसी)। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के केंद्र सरकार पर वोट चोरी के आरोपों ने देशभर में बयानबाजी का बाजार गर्म कर रखा है। ऐसे में अब इस मामले में महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने राहुल गांधी के आरोपों को खारिज करते हुए बेमतलब और बेतुका बताया। पवार ने कहा कि विपक्षी दल ऐसे मुद्दे सिर्फ चुनाव हारने के बाद ही उठाते हैं। पवार ने ये बात नागपुर एयरपोर्ट पर एनसीपी के चिंतन शिविर से पहले पत्रकारों से बातचीत के दौरान कही। बता दें कि वोट चोरी के आरोपों को लेकर एक बार फिर गुरुवार को राहुल गांधी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ज्ञानेश कुमार ने उन लोगों को बचा रहे हैं जिन्होंने लोकतंत्र को नष्ट किया है। उन्होंने कर्नाटक की एक विधानसभा सीट का हवाला देते हुए दावा किया कि कांग्रेस समर्थकों के वोट चुनाव से पहले योजनाबद्ध तरीके से हटाए जा रहे हैं। साथ ही, राजुरा सीट में वोटरों को ऑटोमैटिक सॉफ्टवेयर के जरिए फर्जी तरीके से जोड़े जाने का आरोप भी लगाया। राहुल गांधी के इन आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए अजीत पवार ने कहा कि राहुल गांधी की बातों का कोई मतलब नहीं है। जब लोकसभा चुनाव के दौरान महाराष्ट्र की 48 में से 17 सीटें महायुति को और 31 सीटें महा विकास अघाड़ी को मिली थीं। तब ईवीएम ठीक काम कर रही थी, वोटों की गिनती सही थी और किसी ने नाम जोड़ने या हटाने की कोई शिकायत नहीं की थी। अब जब हार हो गई है, तो नए–नए आरोप लगाए जा रहे हैं। यह बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उन्होंने राहुल गांधी के आरोपों को अनुचित बताया और कहा कि बार–बार हार के बाद चुनाव प्रणाली को कटघरे में खड़ा करना लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। पवार ने आगे कहा कि इंडिया गठबंधन ने कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश में जीत हासिल की थी। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में तीसरी बार सरकार बनाई। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में दो बार और पंजाब में एक बार जीत दर्ज की। अगर चुनाव आयोग पक्षपाती होता, तो ये जीत संभव नहीं होती। अजीत पवार ने यह भी कहा कि 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में संविधान बदलने की झूठी अफवाहों का जवाब जनता ने दिया ।

पूर्व केंद्रीय मंत्री की फेसबुक पोस्ट की जांच में अमेरिका की मदद लेगी पुलिस

तिरुवनंतपुरम, (एजेंसी)। केरल सरकार ने राज्य पुलिस को पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर के फेसबुक अकाउंट की जांच में अमेरिका से मदद लेने की मंजूरी दे दी है। यह मंजूरी अमेरिका से पारस्परिक कानूनी सहायता के तहत दी गई है। केरल भाजपा अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने विवादित फेसबुक पोस्ट 29 अक्टूबर 2023 को कलामस्सेरी में हुए दोहरे बम विस्फोटों को लेकर की थी, जिसमें आठ लोग मारे गए थे। इस पोस्ट को लेकर एर्नाकुलम साइबर सेल में 31 अक्तूबर 2023 को पुलिस ने शिकायत दर्ज

कराई गई थी। प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है कि चंद्रशेखर के अकाउंट से कथित तौर पर किए गए फेसबुक पोस्ट में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की गई और कलामस्सेरी में हुए विस्फोटों में फलस्तीनी आतंकवादी समूह हमास का जिक्र करते हुए एक भड़काऊ टिप्पणी की गई। इस पोस्ट में कांग्रेस और माकपा पर तुष्टिकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया गया और हैशटैगका इस्तेमाल किया गया। इसमें कथित तौर पर हमास नेता खालिद मशाल की ओर इशारा किया गया था, जो विस्फोट से एक दिन पहले केरल में आयोजित फलस्तीन समर्थक विरोध प्रदर्शन में वर्चुअल रूप से शामिल हुआ था। इस पोस्ट की जांच के लिए राज्य पुलिस को अमेरिका में फेसबुक और एक्स मीडिया प्लेटफॉर्म से जानकारी जुटाने की जरूरत है। इस संबंध में पुलिस ने राज्य सरकार से जुलाई में इसकी इजाजत मांगी, जिस पर 8 सितंबर को सरकार ने इजाजत दे दी। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि पारस्परिक कानूनी सहायता का अनुरोध सीबीआई के माध्यम से भेजा जाएगा, जो भारत की इंटरपोल नोडल एजेंसी है। अमेरिका में इंटरपोल एजेंसी संबंधित सोशल मीडिया फर्मों से जानकारी एकत्र करके अनुरोध को आगे बढ़ाएगी।

माझी लाडकी बहिन योजना के लाभार्थियों को ई–केवाईसी कराना अनिवार्य

मुंबई, (एजेंसी)। महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना के लाभार्थियों के लिए ई–केवाईसी अनिवार्य कर दिया है। लाभार्थियों को यह प्रक्रिया पूरी कने के लिए दो महीने का समय दिया गया है। इसको लेकर गुरुवार को एक सरकार आदेश जारी किया गया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना के तहत 21 से 65 वर्ष की उम्र की उन महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपये की मदद की जाती है, जिनके परिवार की सालाना आया 2.5 लाख से अधिक नहीं होती। महिला एवं बाल विकास

मंत्री अदिति तटकरे ने गुरुवार को कहा, योजना के सभी लाभार्थियों के लिए ई–केवाई की सुविधा वेब पोर्टल पर उपलब्ध कराई गई है। आपसे अनुरोध है कि अगले दो महीने के भीतर ई–केवाई की प्रक्रिया पूरी करें। उन्होंने एक्स पर कहा, यह प्रक्रिया आसान और सुविधाजनक है। योजना में पारदर्शिता बनाए रखने और पात्र महिलाओं को नियमित लाभ सुनिश्चित करने के लिए सभी को इसे पूरा करना चाहिए। तटकरे ने कहा कि यह प्रक्रिया भविष्य में अन्य सरकारी योजनाओं के लाभ लेने में भी मददगार होगी। सरकारी आदेश के मुताबिक, महिलाओं को अपनी सत्यापन और प्रमाणीकरण प्रक्रिया दो महीने के भीतर पूरी करनी होगी, ताकि उनके बैंक खातों में मासिक सहायता जारी रहे। आदेश में कहा गया, अगर आधार सत्यापन नहीं किया गाय तो लाभ रोक दिए जाएंगे। लाभार्थियों को हर साल ई–केवाईसी प्रक्रिया अनिवार्य रूप से पूरी करनी होगी। राज्य सरकार ने हाल ही में यह भी बताया था कि करीब 26.34 लाख अपात्र भी योजना में नामांकन कर मासिक सहायता हासिल कर रहे थे, जिनमें पुरुष भी शामिल हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, योजना के तहत अब तक 2.25 करोड़ महिलाएं यह सहायता प्राप्तकर रही है। यह योजना जुलाई 2024 में शुरू की गई थी।

राहुल गांधी ने फिर चुनाव आयोग पर साधा निशाना

नई दिल्ली, (एजेंसी)। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को एकबार फिर से चुनाव आयोग पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग का नाम लिए बिना कहा कि चुनाव का चौकीदार जागता रहा, चोरी देखता रहा। उनकी यह टिप्पणी वोट चोरी के मुद्दे पर अपने हमले को तेज करने के एक दिन बाद आई है। जिसमें उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर लोकतंत्र को नष्ट करने वालों को रक्षा करने का आरोप लगाया था। राहुल गांधी ने कल की अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस का 36 सेकेंड का वीडियो साझा करते हुए लिखा कि सुबह 4 बजे उठो, 36 सेकंड में 2 वोटर मिटाओ, फिर सो जाओ – ऐसे भी हुई वोट चोरी! चुनाव का चौकीदार जागता रहा, चोरी देखता रहा, चोरों को बचाता रहा। गांधी 36 सेकंड के वीडियो में कथित वोट चोरी की कार्यप्रणाली के

बारे में बता रहे हैं। इससे पहले गुरुवार शाम को एक पोस्ट में राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा था कि देश के युवा, देश के छात्र, देश की जेन जी, संविधान की रक्षा करेंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी रोकेंगे। मैं हमेशा उनके साथ खड़ा हूं। जय हिंद! प्रेस वार्ता के बाद राहुल गांधी ने देर शाम सोशल मीडिया पर कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को बहाने बनाना बंद करके सबूत कर्नाटक सीआईडी को तुरंत देने चाहिए। राहुल ने कहा कि जब कांग्रेस के अलंद के उम्मीदवार ने धोखाधड़ी का पर्दाफाश किया, तो स्थानीय चुनाव आयोग के अधिकारी ने प्राथमिकी दर्ज की, लेकिन सीआईडी जांच को सीईसी ने रोक दिया। कर्नाटक सीआईडी ने 18 महीनों में 18 पत्र लिखकर सभी सबूत मांगे, लेकिन सीईसी ने उन्हें रोक दिया।कर्नाटक चुनाव आयोग ने जांच के लिए ईसीआई से कई बार अनुरोध किया, लेकिन सीईसी ने उसे भी रोक दिया।नाम डिलीट करने वाले डेस्टिनेशन आईपी, डिवाइस पोर्ट और ओटीपी के विवरण को छिपाया गया है सीईसी ने इसे रोक दिया। अगर यह वोट चोरी पकड़ी नहीं जाती और 6,018 वोट डिलीट हो जाते, तो कांग्रेस का उम्मीदवार चुनाव हार सकता था।

संपादकीय

पराली की कसक

निर्विवाद रूप से पर्यावरण प्रदूषण देश के सामने एक बड़ा संकट है। लाखों लोगों के जीवन पर इससे संकट के बादल मंडराते हैं। शीत ऋतु की दस्तक के साथ राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण की काली छाया के बीच अक्सर इस संकट के मूल में निकटवर्ती राज्यों में पराली जलाने की घटनाओं को जिम्मेदार बताने की कवायद हर साल होती है। इस बार भी पंजाब में धान की खरीद शुरू होने के बाद विभिन्न हितधारकों का ध्यान एक मौसमी समस्या पराली जलाने की ओर आकर्षित हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से उस कुप्रथा में लिप्त कुछ किसानों को गिरफ्तार करने के बारे में निर्णय लेने को कहा है, जिसे हर साल अक्टूबर–नवंबर में वायु प्रदूषण का एक प्रमुख कारण बताया जाता है। वैसे न्यायालय ने इस बात को स्वीकार किया है कि 'हमारे लिये किसान विशेष हैं और हम उनकी बदौलत ही भोजन प्राप्त कर रहे हैं। साथ ही अपनी खाद्य श्रृंखला को मजबूत कर रहे हैं।' लेकिन वहीं दूसरी ओर शीर्ष अदालत ने राज्य से पर्यावरण की सुरक्षा के बारे में कड़ा संदेश देने के लिये दंडात्मक प्रावधान लागू करने का भी आग्रह किया है। निर्विवाद रूप से देश में पंजाब और हरियाणा, जो कि खाद्यान्न उत्पादन में अग्रणी राज्य भी हैं, पराली जलाने से रोकने के लिये विगत में कभी–कभी किसानों को जेल में भी डालते रहे हैं। लेकिन एक हकीकत यह भी है कि यह कठोर कदम व्यावहारिक धरातल में एक प्रभावी निवारक साबित नहीं हो सका है। हमें इस बात की भी अनदेखी नहीं करनी चाहिए कि पिछले कुछ वर्षों में हुई गिरफ्तारियों और भारी जुर्माने ने इस क्षेत्र के कृषक समुदाय के गुस्से को भड़काया ही है। जिसने केंद्र और राज्य सरकारों के खिलाफ आवाज उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। वैसे एक हकीकत यह भी है कि सत्ताधीशों के लिये किसानों पर आपराधिक मुकदमा चलाना राजनीतिक दृष्टि से एक जोखिम भरा कदम माना जाता है। निस्संदेह, इन राज्यों में किसान अब एक प्रभावशाली वोट बैंक बन चुके हैं। खासकर पंजाब में किसानों की जागरूकता सत्ताधीशों पर दबाव बनाने में कामयाब हो जाती है। सर्वविदित है कि देश के सीमावर्ती राज्य पंजाब में हाल ही में आई बाढ़ के दौरान धान की फसल को भारी नुकसान पहुंचा है। ऐसे में किसानों के खिलाफ कोई सख्त कदम उठाना संवेदनशीलता की दृष्टि से उचित भी नहीं कहा जा सकता है। इसलिए अधिकारी किसी संभावित आक्रोश से बचने के लिये दंडात्मक कार्रवाई से बचने का प्रयास कर सकते हैं। ऐसे में वे कोई सुरक्षित रुख अपना सकते हैं। निस्संदेह, किसी ऐसी सख्त कार्रवाई से पहले ही प्राकृतिक आपदा की मार झेल रहे किसानों की स्थिति और बिगड़ सकती है। ऐसे हालात में किसानों से टकराव की बजाय सहयोग को प्राथमिकता बनाना तार्किक कहा जा सकता है। आर्थिक विकल्प, दंड से बेहतर काम करेगा। दूसरी ओर किसानों को पराली के प्रबंधन के लिए प्रोत्साहित करने की जरूरत है। हम उन्हें सशक्त बनाकर इस संकट का तार्किक समाधान निकाल सकते हैं। सरकार प्रयास करे कि पराली का उपयोग उद्योगों द्वारा जैव ईंधन के रूप में एक उत्पादक विकल्प के तरह किया जाए। हमारे देश के ऊर्जा उत्पादन में बायोमास के उपयोग को बढ़ावा देने से जमीनी स्तर पर बदलाव लाया जा सकता है।

रक्षा आत्मनिर्भरता के लिए जरूरी अधिक वित्तीय संसाधन

अंकित

ऑपरेशन सिंदूर ने हमारे सशस्त्र बलों के बीच अधिक एकीकरण और आत्मनिर्भरता पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता को रेखांकित किया है। इस संदर्भ में हाल ही में कोलकाता में संयुक्त कमांडरों को प्रधानमंत्री का संबोधन कई दृष्टिकोणों से महत्वपूर्ण है। हालांकि रक्षा उत्पादों में आत्मनिर्भरता के लिए वित्तीय आवंटन बढ़ाना भी जरूरी है। कोलकाता में 15 सितंबर को आयोजित 16वें संयुक्त कमांडर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन में दिया एक संदर्भ बहुत अहम है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह पहली बार था जब प्रधानमंत्री सेना के शीर्षस्थ अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे। जहां इस ऑपरेशन को बड़ी सफलता के रूप में सराहा गया– चंद आरंभिक असफलताओं के बावजूद – वहीं इसने भारत की सुरक्षा के शीर्ष निधारिकों के विचारार्थ एक नई सामान्य और परिचालन चुनौती पेश की है। वह है, परमाणु ब्लैकमेल एवं आतंकवाद के बीच संबंध– एनडब्ल्यूईटी (परमाणु हथियार सक्षम आतंकवाद) सिंड्रोम – और ऐसे कई अन्य पहलू, जिन पर उद्देश्यपूर्ण समीक्षा करने की जरूरत है। ऑपरेशन सिंदूर अभी समाप्त नहीं हुआ और जारी है, अर्थात सेना अभी भी चौकस है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान नए क्षेत्रीय भू–राजनीतिक और रणनीतिक नाते सामने आए, विशेष रूप से चीन–पाकिस्तान सहयोग, जो अब सामरिक गठबंधन का रूप धर चुका है और इस जुगलबंदी से अगली किसी युद्धक आपात स्थिति में नई चुनौतियां उत्पन्न हो सकती हैं। इसके अलावा, टैरिफ को लेकर अमेरिका के साथ द्विपक्षीय संबंधों में हालिया तनाव ने समुद्री क्षेत्र में सहयोग के भविष्य को लेकर, खासकर क्वाड का भविष्य, काफी अनिश्चितता खड़ी कर दी। हालांकि, इन जटिलताओं और चुनौतियों पर इस सम्मेलन में चर्चा नहीं की गई और प्रधानमंत्री का संबोधन (जैसा कि प्रेस सूचना विभाग द्वारा जारी किया गया) का सार अपेक्षाकृत संक्षिप्त था – मात्र 275 शब्दों का। इसकी इबारत चिर–परिचित थी और विषयवस्तु रक्षा सुधारों, परिचालन तत्परता और उभरते सुरक्षा परिदृश्य पर केंद्रित रहा। साल 2025 के इस सम्मेलन का मुख्य विषयवस्तु था 'सुधारों का वर्ष – भविष्य के लिए रूपांतरण' और इसके लिए संयुक्तता, आत्मनिर्भरता और नवाचार पर चर्चा हुई। मोदी के आह्वान का निहितार्थ महत्वपूर्ण और निर्देशात्मक है, कि उन्होंने रक्षा मंत्रालय को थल सेना, नौसेना और वायु सेना के बीच 'अधिक एकीकरण' (जोर दिया शब्द बाद में जोड़ा गया) बनाने की पहलों में तेजी लाने और स्वदेशी तकनीक एवं नवोन्मेष को बढ़ावा देने का निर्देश दिया। वहीं यह भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में मिली सफलता तीनों सेनाओं के बीच तालमेल का प्रमाण है। ये दो नीतिगत मुद्दे, जैसे युद्ध क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए तीनों सशस्त्र बलों के बीच अधिक संयुक्तताय और आत्मनिर्भरता में स्पष्ट दिखाई देने वाली प्रगति। यह दोनों 2014 में पदभार ग्रहण करने के बाद से ही मोदी के ध्यान में रहे और इसके लिए की गई प्रमुख पहलों का श्रेय उन्हें जाता है। इनमें, 2019 में सीडीएस (चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ) पद का सृजन और रक्षा मंत्रालय में डीएमए (सैन्य मामलों का विभाग) की स्थापना शामिल है ताकि भूलभुलैया सी जटिल निर्णय प्रणाली में वर्दीधारी बिरादरी की भागीदारी भी हो सके। हालांकि, इन दोनों निर्णयों के परिणाम उस तरह का नहीं रहा, जिसकी परिकल्पना बनाते समय की गई थी और इसपर पीएम मोदी के कोलकाता संबोधन के संदर्भ में प्रारंभिक समीक्षा को तरजीह देना बनता है। कमानों के बीच एकता, बहुत सम्मानित सैन्य सिद्धांत रहा है, लेकिन भारतीय संदर्भ में, 1965 से यह तीनों सशस्त्र बलों के बीच तीखी बहस का विषय रहा। सार यह कि जहां थलसेना इसकी प्रबल समर्थक है और नौसेना इस अवधारणा का अनुमोदन करती है वहीं वायु सेना को मोदी सरकार द्वारा बनाई गई उस रणभूमि संयुक्त कमान व्यवस्था पर किंतु–परंतु है। भारत ने सितंबर 2024 में लखनऊ संयुक्त कमांडर सम्मेलन (जेसीसी) के दौरान औपचारिक रूप से एकीकृत युद्ध संचालन कमान (आईटीसी) की स्थापना की घोषणा की थी, जिसमें सशस्त्र बलों ने तीन प्रस्तावित आईटीसी – उत्तरी (चीन पर केंद्रित), पश्चिमी (पाकिस्तान पर केंद्रित), और समुद्री (हिंद महासागर क्षेत्र के लिए) बनाने का विस्तृत खाका और तौर–तरीके सरकार की मंजूरी के लिए पेश किए थे। हालांकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद, वायुसेनाध्यक्ष एपी सिंह ने उस मौजूदा व्यवस्था में आमूल–चूल परिवर्तन करने के प्रति आगाह किया है, जिसमें प्रत्येक सेवा प्रमुख का अपने तहत आते बल पर पूर्ण परिचालन नियंत्रण है। अनेक सैन्य सामग्री की कमियों से जूझ रही वायुसेना की क्षमता, जिसने भारतीय वायु शक्ति को घटा रखा है, इस पर 'जब कुछ टूटा ही नहीं है, तो जोड़ना किसको है?' वाली कहावत लागू होती दिखाई देती है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को वर्तमान परिचालन व्यवस्था (कुल 17 सैन्य कमानों का मिला–जुला अंतर–सेना मंच) के संतोषजनक ढंग से काम को मिसाल के रूप में देखा जा रहा है। मौजूदा सैन्य कमान संरचनाओं को युक्तिसंगत बनाने की आवश्यकता कोई नया मुद्दा नहीं और यहां याद किया जा सकता है कि मनमोहन सिंह ने 2013 के अंत में संयुक्त कमांडरों को बतौर प्रधानमंत्री अपने अंतिम संबोधन में 'उच्च रक्षा प्रबंधन हेतु सही संरचनाओं की स्थापना और हमारी जटिल सुरक्षा की मांग के अनुरूप निर्णय लेने में समुचित नागरिक–सैन्य संतुलन स्थापना में तत्काल एवं ठोस प्रगति' की जरूरत पर बल दिया था। उन्होंने आगे कहा थारू 'मैं आपको इसपर सर्वोच्च पेशेवराना चिंतन करने, विभिन्न रक्षा सेवाओं के बीच मतभेदों पर सहमति बनाने और भविष्य के लिए रूपरेखा तैयार करने को प्रोत्साहित करता हूं। मैं विश्वास दिलाता हूं कि राजनीतिक नेतृत्व आपकी सिफारिशों पर अत्यंत सावधानीपूर्वक विचार करेगा'। उम्मीद है, इस मुद्दे को आंतरिक रूप से सुलझा लिया जाएगा और निकट भविष्य में एक सर्वसम्मत समाधान निकल आएगा। यह मुद्दा जटिल और बहुस्तरीय है और पेशेवर फौज और विधायिका, दोनों के बीच इसपर बेबाक और सूचनायुक्त नीतिगत चिंतन किए जाने की जरूरत है। रक्षा साजो–सामान में आत्मनिर्भरता बनाना एक पुराना ध्येय है और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1980 के दशक की शुरुआत में सीसीसी और डीआरडीओ को स्वदेशी प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया था और यहीं से आईजीएमडीपी (एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास परियोजना) की उत्पत्ति हुई,।

हिमालयी राज्यों के अस्तित्व पर मंडराता संकट

सुनिल

हिमालयी राज्यों के लिए अब विकास और संरक्षण का प्रश्न नहीं, बल्कि अस्तित्व बचाने का है। यदि तुरंत कार्रवाई नहीं हुई, तो यह संकट न सिर्फ पर्यावरण, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के जीवन और संस्कृति को भी प्रभावित करेगा। इस वर्ष की भारी वर्षा ने उत्तराखंड में विनाश की झलक दिखा दी, जबकि हिमाचल प्रदेश भी उसी संकट की छाया में है। बादल फटना, भूस्खलन, ग्लेशियरों का पिघलना और अवैज्ञानिक निर्माण ने इन हिमालयी राज्यों को त्रासदी की ओर धकेल दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने हिमाचल को चेताया भी है कि 'वह दिन दूर नहीं जब पूरा राज्य नक्शे से मिट सकता है।' यह चेतावनी उत्तराखंड पर भी समान रूप से लागू होती है। यह संकट पूरे हिमालयी क्षेत्र के लिए एक गंभीर संकेत है। हिमालयी राज्यों की सबसे बड़ी त्रासदी का कारण अनियंत्रित निर्माण है। उत्तराखंड में 4,000 से अधिक होटल और गेस्टहाउस नदियों के प्राकृतिक बाढ़ मार्गों पर बने हैं, जो बाढ़ के समय सबसे पहले ध्वस्त होते हैं और तबाही को कई गुना बढ़ा देते हैं। केवल 'नो कंस्ट्रक्शन जोन' घोषित कर इन ढांचों को चरणबद्ध हटाना ही हजारों जीवन बचा सकता है। वहीं चारधाम यात्रा में हर साल लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं, जबकि हिमाचल के प्रमुख मंदिरों में सवा करोड़ से अधिक श्रद्धालु आते हैं। तंग घाटियां और नाजुक रास्ते इस भारी दबाव को सहन नहीं कर पाते हैं। इसके परिणामस्वरूप जाम, कचरे के ढेर और बरसात के दौरान गंभीर दुर्घटनाएं होती हैं। इसलिए डिजिटल परमिट जारी कर दैनिक श्रद्धालुओं की संख्या को सीमित कर देना अनिवार्य है। इसम समय उत्तराखंड में 150 से अधिक और हिमाचल में 170 से अधिक बड़ी जलविद्युत परियोजनाएं मंजूर की गई हैं, जिनमें विस्फोट और सुरंग बनाने के कारण पहाड़ अस्थिर हो रहे हैं। इसके विपरीत, 100दृ200 किलोवाट क्षमता के छोटे हाइड्रोप्रोजेक्ट बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए स्थानीय जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। अक्सर कंक्रीट के बांध तेज बहाव में टूट जाते हैं और बाढ़ का रूप ले लेते हैं। ऐसे में पेड़–पौधों और घास की प्राकृतिक दीवारें सस्ती, टिकाऊ और अधिक प्रभावी होती हैं। यह तरीका जापान और स्विट्जरलैंड में सफल रहा है। इससे क्षरण में 70 प्रतिशत तक की कमी आई है। इस समय हिमालय की 16,000 बस्तियों में 500 से भी कम जगह चेतावनी प्रणाली है। बादल फटने जैसी घटनाओं में लोग बिना सूचना के मारे जाते हैं। ऐसे में हर घाटी में स्वचालित स्टेशन और मोबाइल अलर्ट जान बचा सकते हैं। अक्सर देखा गया है कि अधिकांश निर्णय राजधानी में लिए जाते हैं, जिनका जमीनी स्तर पर कोई अनुभव नहीं होता। लेकिन खतरे को सबसे पहले पहाड़ों के निवासी महसूस करते हैं। यदि गांव और वन पंचायतों को अतिरिक्त अधिकार दिया जाएं, तो खतरनाक परियोजनाओं को शुरू करने से पहले रोका जा सकता है। हाल ही में अगस्त में उत्तरकाशी के धराली में बादल फटने से क्षीर गंगा पथरीली सैलाब बनकर उमड़ी और घर, होटल तथा सेना के कैंप को बहा ले गई। हर्षिल में पुल ढह गए, बाजार बह गए और बैरक डूब गए। सड़कें बंद हो गईं, हेलिकॉप्टर उड़ान भरने में असमर्थ रहे और लोग पानी में अपने परिजनों को खोजते रहे। वर्ष 2024 में 1,813 भूस्खलन हुए। 1988 से अब तक 12,000 से अधिक भूस्खलन दर्ज हुए हैं। उत्तराखंड को लगभग 6,000 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ। उत्तराखंड में करीब 150 से अधिक हाइड्रो प्रोजेक्ट्स के लिए पहाड़ों को तोड़ा जाना, नदियों का मार्ग बदलना, सड़कों का चौड़ीकरण और अनियंत्रित होटल निर्माण ने पहाड़ों को अस्थिर बना दिया है।

.... विविध ....

घूमना नहीं, समझना है पर्यटन का मकसद

अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस पर्यटन के व्यापक महत्व को समर्पित है। यह केवल यात्रा नहीं, बल्कि आर्थिक प्रगति, सांस्कृतिक आदान–प्रदान, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक मेलजोल को बढ़ावा देने का जरिया है। सतत विकास और जिम्मेदार पर्यटन की दिशा में यह हमें प्रेरित करता है। पर्यटन रोजगार सृजन, तकनीकी नवाचार और स्थानीय समुदायों के आर्थिक सशक्तीकरण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हर साल 27 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत साढ़े चार दशकों पहले सनद्द 1980 में संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा की गई थी। इस दिन को एक वैश्विक पर्यटन डे के रूप में सेलिब्रेट किये जाने के पीछे मकसद यह है कि आज पर्यटन महज घूमने, फिरने की गतिविधिभर नहीं है। आज पर्यटन वैश्विक अर्थव्यवस्था, पर्यावरण संरक्षण, विभिन्न संस्कृतियों के रहवासियों के बीच संवाद और सामाजिक मेलजोल बढ़ाने के साथ–साथ दुनिया के बारे में एक बेहतर समझ विकसित करने का जरिया भी है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस इस बात की याद दिलाता है कि दुनिया को खूबसूरत बनाने और बनाये रखने के लिए हम सभी दुनिया वालों की मिलकर साझी भूमिका हो सकती है और यह तभी संभव है, जब हम एक–दूसरे से मिलें–जुलें, एक–दूसरे के यहां आएं–जाएं और एक–दूसरे को गहराई से जाने–समझें तथा सबसे जरूरी है कि एक–दूसरे का सम्मान करें। यह सब तभी संभव है, जब सकारात्मक दिलोदिमाग से बिना कोई पूर्वाग्रह पाले हुए और बिना किसी श्रेष्ठता ग्रंथी को ढोते हुए, दुनिया और दुनिया वालों को प्यार करें, सम्मान करें और सबकी महत्ता को समझें। यह सब पर्यटन से ही संभव है इसलिए आज पर्यटन एक हॉबीभर नहीं होनी चाहिए बल्कि दुनिया की सुख, शांति और समृद्धि का जरिया होना चाहिए।

केवल घुमक्कड़ी नहीं, बहुआयामी क्षेत्र

हम क्यों कहते हैं कि सिर्फ घूमना, फिरना भर पर्यटन नहीं है, दरअसल पहले ऐसा ही था। नई नई जगहें देखने को घुमक्कड़ी या पर्यटन समझा जाता था। लेकिन आज यह एक बहुआयामी है। यह न केवल घूमने आने वाले घुमक्कड़ों को सुख का अनुभव कराता है बल्कि जहां लोग घूमने गये होते हैं, उन जगहों और देशों की यह घुमक्कड़ी आर्थिक किस्मत भी तय करती है। क्योंकि आज पर्यटन रोजगार का एक विशाल क्षेत्र है। आज पर्यटन विदेशी मुद्रा अर्जित करने का भी एक बड़ा जरिया है। यह सांस्कृतिक आदान–प्रदान और कूटनीति का माध्यम तो है ही, ग्रामीण विकास और उद्यमियता को भी गति देता है। पर्यटन गतिविधि के जरिये प्राकृतिक और सांस्कृतिक धरोहरों की रक्षा करने को हम प्रेरित होते हैं।

विकास की प्रक्रिया का हिस्सा

शायद इसीलिए हर साल पर्यटन दिवस को एक नये उत्साह और प्रेरणा से सेलिब्रेट करने के लिए हर साल के सेलिब्रेशन की एक थीम विशेष होती है। साल 2025 की थीम हैकृ'टूरिज्म एंड सस्टेनेबल ट्रांसफार्मेशन' इस थीम का उद्देश्य है पर्यटन को सतत परिवर्तन की दिशा में ले जाना जिससे पर्यावरण की रक्षा, स्थानीय समुदायों की खुशहाली, तकनीकी और नवाचार एक साथ मिलकर आगे बढ़ें। यह उद्देश्य हमें याद दिलाता है कि पर्यटन सिर्फ एक मनोरंजन या आर्थिक गतिविधि नहीं है बल्कि यह एक जिम्मेदार, समावेशी और टिकाऊ विकास की प्रक्रिया का हिस्सा बन चुका है। इस साल के अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस की यह थीम हमें प्रेरित करती है कि हम पर्यावरण संरक्षण और ग्रीन टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने का पर्यटन को जरिया बनाएं और स्थानीय समुदायों को इस प्रक्रिया से जोड़कर उनका आर्थिक सशक्तीकरण करें। डिजिटल नवाचार और स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिये हम आज पर्यटन को पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित, सुखद और सहज बना सकते हैं। इसके लिए जिस बात का ध्यान रखना सबसे जरूरी है, वह यह है कि हम एक पर्यटक के रूप में अपनी जिम्मेदार यात्राओं की आदत डालें। अंधाधुंध और बेतहाशा संसाधनों के उपभोग से बचें और पर्यटन का आनंद लेते हुए इस बात का ध्यान रखें कि जो चीजें हमें सुख दे रही हैं, जिनके जरिये हम खुश हैं, वे आखिर किसी की संपत्ति है, इसलिए उनकी सुरक्षा करना भी हमारा दायित्व है। जब हम कहीं घूमने जाकर वहां के ऐतिहासिक धरोहरों को सिर्फ रोमांस की नजरों से निहारतेभर नहीं बल्कि रोमांच बरकरार रखने को धरोहरों का सम्मान भी करते हैं और इसके लिए संवेदनशीनलता भी दर्ज करते हैं, तो हम न केवल पर्यावरण अनुकूल और सकारात्मक पर्यटक होते हैं बल्कि इससे हम उन लोगों की मदद भी करते हैं, जहां पर्यटन हेतु गये होते हैं। लेकिन जब हम इस भाव से यात्रा करते हैं कि हमने पैसा खर्च किया है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा संसाधनों का उपभोग कर लें तो हम इकोफ्रेंडली पर्यटक नहीं होते। फिर हमसे दुनिया समृद्ध नहीं होती बल्कि हमारी गतिविधियों से दुनिया को ठेस पहुंचती है। इसलिए पर्यटन को मानवीय, संवेदनशील और स्थानीय लोगों के साथ मित्रवत बनाये रखने के लिए हमें अपनी पर्यटक के रूप में न सिर्फ छवि सुधारनी होगी। अपना आचरण को भी आत्मीय बनाना होगा।

वैश्विक अर्थव्यवस्था में पर्यटन

दुनिया में तेल और हाल के सालों में उभरे आईटी क्षेत्र के बाद अगर सबसे बड़ा कोई उद्योग है, सबसे ज्यादा राजस्व हासिल करने का क्षेत्र है, तो वह यही पर्यटन उद्योग है। दुनिया का तीसरे नंबर का सबसे महत्वपूर्ण उद्योग पर्यटन आज समूचे विश्व की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। संयुक्त राष्ट्र की एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के सकल घरेलू उत्पाद में पर्यटन उद्योग की भूमिका 10 फीसदी है। दुनिया में जितने भी लोग नौकरी–पेशे में हैं, उनमें हर दसवें व्यक्ति की नौकरी इसी पर्यटन उद्योग से जुड़ी हुई है। दुनिया में कई ऐसे देश हैं, जिनके पास पर्यटन एकमात्र आजीविका का साधन है और उनकी गिनती दुनिया के समृद्ध देशों में होती है। थाइलैंड, मालद्वीव, मोरक्को और ग्रीस के पास सबसे बड़ा आर्थिक संसाधन पर्यटन उद्योग ही है। नेपाल, भूटान और श्रीलंका जैसे देशों की भी इकोनॉमी का यह मुख्य आधार है।

भारत में पर्यटन का महत्व

भले ही हमारे अपने देश में इसकी विशेष महत्ता न समझी जाती हो, लेकिन साल 2024 के आंकड़े बताते हैं कि भारत में 4 करोड़ लोगों को रोजगार इसी पर्यटन उद्योग के जरिये ही हासिल है और हां, यह भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 8 फीसदी सालाना का योगदान देता है।

जरा कल्पना करिये, जिस देश में 50 फीसदी से ज्यादा लोग आजीविका के लिए खेती से जुड़े हैं और देश के कुल वर्कफोर्स में 45 फीसदी खेती के काम में लगे हैं, उस विशाल संसाधन खेती से जीडीपी में महज 16 फीसदी की भागीदारी सुनिश्चित होती है और जिस पर्यटन उद्योग की आमतौर से चर्चा भी व्यवस्थित तरीके से नहीं होती, वह पर्यटन उद्योग अकेले बिना शोर–शराबा किये हमारे सकल घरेलू उत्पाद में अगर खेती के आधे की भूमिका निभाता है, तो सोचिए पर्यटन उद्योग भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण उद्योग है।

रोजगार, संस्कृति और संवेदनशीलता

आज की तारीख में पर्यटन अर्थव्यवस्था का सचल इंजन बन चुका है। होटल, परिवहन, इवेंट प्रबंधन, हस्तशिल्प, फोटोग्राफी आदि क्षेत्रों से करोड़ों लोगों को रोजगार मिला हुआ है। पर्यटन उद्योग के जरिये देश हर साल भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा अर्जित करता है। पर्यटन उद्योग की बदौलत भारत में हवाईअड्डों, सड़कों, रेलवे, आईटी सेवाएं आदि की सुविधाएं बहुत तेजी से विकसित होती हैं। पर्यटन अर्थव्यवस्था का अब देश की ग्रामीण दुनिया में भी विस्तार हो चुका है। गांव में होम स्टे, एथनिक फूड और हस्तशिल्प को बढ़ावा मिलता है और इन सबसे अलग हमें इस बात को भी नहीं भूलना चाहिए कि पर्यटन सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व की गतिविधि होती हैं यह महज पैसा कमाने का जरिया ही नहीं है बल्कि पर्यटन दो भिन्न संस्कृतियों को भी आपस में जोड़ता है।

कला–शिल्प का विराट उत्सव भी

शारदीय नवरात्रि भारत में नौ दिनों तक मनाया जाने वाला महत्वपूर्ण त्योहार है। यह केवल देवी पूजा का पर्व नहीं, बल्कि सांस्कृतिक उत्सव, लोकनृत्य, संगीत, कला और सामाजिक मेलजोल का भी उत्सव है। देश के विभिन्न हिस्सों में इसे अलग–अलग रूपों में भव्यता से मनाया जाता है। भारत विविधताओं का देश है। यहां पर हर पर्व केवल पूजा–पाठ तक सीमित नहीं रहता बल्कि वह समाज की सांस्कृतिक धड़कन बनकर हमारे लोकजीवन को गतिमान बनाये रखता है। शारदीय नवरात्रि इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। नौ दिनों का यह पर्व देश के अलग–अलग हिस्सों में अलग–अलग रूपों और परंपराओं के साथ मनाया जाता है। हालांकि, धार्मिक आस्था सभी परंपराओं के केंद्र में होती है। मगर इसकी छाया में कहीं लोकनृत्य, कहीं संगीत, कहीं खानपान और कहीं कला का ऐसा सामूहिक उत्स उमड़ता है कि शारदीय नवरात्रि विशिष्ट सांस्कृतिक मंच बन जाते हैं। ग्रामीण भारत में नवरात्रि का समय खेतों और घरों में नये उम्मीदों का मौसम लाता है। मानसून की फसलें पकने लगती हैं और किसान नये कामों की योजनाएं बनाने लगते हैं। यही कारण है कि नवरात्रि के अवसर पर गांवों में मेलों, रामलीलाओं और भजन मंडलियों का विशेष धमाल देखने को मिलता है। नवरात्रि केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं है बल्कि सामाजिक मेलजोल और सांस्कृतिक उत्सव भी हैं। इन नवरात्रि का सबसे भव्य रूप बंगाल में देखने को मिलता है, जहां इसे दुर्गा पूजा कहा जाता है। इस अवसर पर कोलकाता और बंगाल के दूसरे शहरों, कस्बों और गांव–गांव में देवी मां के पंडाल सजते हैं, जहां मां की भव्य प्रतिमाएं स्थापित होती हैं। कलाकार महीनों पहले इन प्रतिमाओं की तैयारी करते हैं। पंडालों की थीम कभी सामाजिक संदेश होती है, तो कभी किसी ऐतिहासिक स्थल की झलक पेश करती है। पूरे पांच दिन तक पूजा, सांस्कृतिक कार्यक्रम, नृत्य संगीत और भोज उत्सव का आयोजन चलता है। अंत में मां दुर्गा की प्रतिमा की विसर्जन यात्रा निकलती है, जिसमें ढाक की धुन, ढोल, नगाड़े और नृत्य के साथ देवी मां को विदा किया जाता है।

इसी समय गुजरात में गरबा और डांडिया की धूम रहती है। यहां रात–रातभर नृत्योत्सव चलता है। गुजरात में विशेषकर नृत्य, देवी मां की उपासना का जरिया होता है। गरबा की गोल–गोल घूमती तालियां, रंग–बिरंगे परिधान, दीयों की मनमोहक लौ और शक्ति की भक्ति में डूबे भक्त, उत्सव के आनंदातिरेक में होते हैं। वास्तव में गुजरात में भक्ति और शक्ति के मिलन का उत्सव मनाया जाता है। उत्तर भारत में रामलीलाएं शारदीय नवरात्रि का सबसे बड़ा सांस्कृतिक आकर्षण हैं। नौ दिनों तक यहां गांव–गांव में, शहर–शहर में रामलीलाओं का मंचन होता है, जहां साधारण ग्रामीण जनों से लेकर मशहूर और व्यावसायिक कलाकार तक इसमें हिस्सेदारी करते हैं। मंच पर राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान के रूप धरे कलाकार जब डूबकर अभिनय करते हैं, तो दर्शक भक्ति रस में डूब जाते हैं। दसवीं के दिन यहां रावण दहन के साथ शारदीय नवरात्रि का उत्सव चरम पर पहुंच जाता है। यह परंपरा न केवल समाज को एक सूत्र में पिरोती है बल्कि नई पीढ़ी को नैतिक और धार्मिक शिक्षा भी देती है। शारदीय नवरात्रि के समय भारत के अलग–अलग क्षेत्रों में विशिष्ट लोकगीतों की गूंज रहती है। कहीं देवी मां के जागरण का स्वर दमकता है, तो कहीं भजन मंडलियां पूरे वेग से भजनों में रमी होती हैं। राजस्थान और हरियाणा में घर घर देवी मां के गीत गूंजते हैं। कुल मिलाकर शारदीय नवरात्रि पूरे देश में धार्मिक, आस्था और सामाजिक भागीदारी का विशिष्ट आयोजन होते हैं।

थानीय समस्याओं के त्वरित समाधान और जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन पर जोर

लखनऊ, (संवाददाता)। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने गुरूवार को जनपद बहराइच का भ्रमण किया और कलेक्ट्रेट सभागार में जनपद स्तरीय समस्त विभागों के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की। बैठक में उप मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि तहसील स्तर पर एसडीएम, सीओ और विद्युत विभाग के अधिकारी प्रत्येक माह जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में बैठक आयोजित कर स्थानीय समस्याओं का त्वरित समाधान करें।स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान निर्देश दिए गए कि अभियान चलाकर सभी सीएचसी, पीएचसी और स्वास्थ्य केन्द्रों में नियमित स्वच्छता सुनिश्चित की जाए। स्वच्छता के प्रति लापरवाह अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके अतिरिक्त सभी कार्यालयों में मासिक एक दिन विशेष स्वच्छता अभियान संचालित किया जाएगा। आयुष्मान कार्ड धारकों को मानक के अनुसार चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी और मेडिकल कॉलेज में सभी संसाधन मुहैया कराए जाएं, ताकि मरीजों और तीमारदारों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।बिजली आपूर्ति की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि स्थानीय फाल्ट और ट्रांसफार्मर की मरम्मत समय से पूरी की जाए और शासन द्वारा निर्धारित रोस्टर के अनुसार आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। विद्युत आपूर्ति के समय में किसी भी प्रकार की समस्या आने पर जनप्रतिनिधियों को जानकारी दी जाए और उनका सहयोग प्राप्त किया जाए।उप मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि अभियान के रूप में अविवादित वरासत के मामले दर्ज किए जाएं, ताकि पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ आश्रितों तक पहुंचे। जनपद में उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाए और जमाखोरी तथा ओवररेटिंग करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए। गन्ना भुगतान समय पर कराया जाए।कानून एवं शांति व्यवस्था की समीक्षा के दौरान असामाजिक तत्वों के विरुद्ध तत्परता के साथ कार्रवाई करने और चोरी की घटनाओं को रोकने के लिए ठोस उपाय करने के निर्देश दिए गए। वन्य जीव प्रभावित क्षेत्रों में 24 घंटे विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने और पीड़ितों का मुआवजा दिलाने के लिए डीएफओ को भी निर्देशित किया गया।बैठक में जिलाधिकारी को निर्देश दिए गए कि जनपद स्तर पर गठित विभिन्न कमेटियों को अद्यतन किया जाए और उनकी नियमित बैठकें आयोजित की जाएं। उप मुख्यमंत्री ने चकमार्गों और चरागाहों को अतिक्रमण मुक्त कर उपयोग में लाने और कछार क्षेत्र का सीमांकन करने के लिए अभियान चलाने के भी निर्देश दिए।पशुपालन विभाग की समीक्षा में बताया गया कि जनपद के गौआश्रय स्थल सीसीटीवी कैमरों से आच्छादित हैं, और उनका कंट्रोल रूम विकास भवन में स्थापित है। उप मुख्यमंत्री ने जनप्रतिनिधियों को सुझाव दिया कि समय–समय पर वे भी कंट्रोल रूम का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लें।प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण और मुख्यमंत्री आवास योजना–ग्रामीण की ।

मां पर एफआईआर के सवाल पर अपर्णा यादव ने दिया जवाब

लखनऊ, (संवाददाता)। उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव शुक्रवार को सुल्तानपुर पहुंचीं। यहां उन्होंने जिला जेल में महिला बंदियों से भेंट किया। उन्होंने बताया यहां पुस्तकालय बन रहा है, मैं उसमें पुस्तकें दूंगी। इसके बाद उन्होंने अपनी मां पर हुए केस के सवाल पर सिर्फ नो कमेंट कहा। उन्होंने राहुल गांधी को निशाने पर लेकर उन पर तंज कसा। हाइड्रोजन बम वाले बयान पर कहा वोट चोरी करना... न करना एक विषय है, कांग्रेस से ज्यादा वोट चोरी

किसने की है? बोफोर्स क्या है? गूगल पर सर्च कर लीजिए, कांग्रेस की पोल खुल जाएगी। फिर, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हुए कई बातें कहीं। कहा कि प्रधानमंत्री ने एक बात जरूर की है कि कि जो लोग आतंकवाद फैला रहे थे, उनकी नींद उड़ा दी है। आज राष्ट्र विरोधियों की नींद बिल्कुल खराब हो गई है। उन्होंने आगे कहा कि राहुल अजीब तरीके से बात करते हैं तो हो सकता है पीएम की तारीफ करने के बजाय वह इस तरह की बात कर रहे हों।

संक्षिप्त खबरें

टैरिफ से बेहाल निर्यातकों को मिल सकता है तीन–चार माह का राहत पैकेज

लखनऊ, (संवाददाता)। यूपी सरकार अमेरिकी टैरिफ से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले क्षेत्रों की ग्राउंड रिपोर्ट तैयार करा रही है। कानपुर, उन्नाव, आगरा, बनारस, मुरादाबाद, भदोही, नोएडा, अलीगढ़, गाजियाबाद, अमरोहा और संभल सहित सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले जिलों में वरिष्ठ अधिकारी जाकर टैरिफ के असर की रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। माना जा रहा है कि इस आधार पर टैरिफ संकट का हल निकलने तक सरकार निर्यातकों को तीन से चार महीने का राहत पैकेज दे सकती है। निर्यातकों से मिले फीडबैक के मुताबिक, अमेरिका की ओर से लगाए गए पहले के 25 फीसदी टैरिफ से इतनी परेशानी नहीं थी, लेकिन अतिरिक्त 25 फीसदी शुल्क ने संकट बढ़ा दिया है। सूत्रों के मुताबिक, निर्यातकों ने मांग की है कि कुल 50 फीसदी में से 15 फीसदी की राहत सरकार से मिल जाए, तो अमेरिकी बाजार में टिके रहना संभव होगा। माना जा रहा है कि सरकार जल्द 13 फीसदी तक की राहत दे सकती है। तीन से चार महीने तक के राहत पैकेज से राज्य सरकार के खजाने पर करीब 400 से 500 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा।

शौकत अली पर चले राष्ट्रद्रोह का मुकदमा

लखनऊ, (संवाददाता)। महाराजा सुहेलदेव पासी के विरुद्ध की गई टिप्पणी से नाराज सरोजनीनगर क्षेत्र के पासी समाज के लोगों ने बृहस्पतिवार को कानपुर रोड स्थित स्कूटर इंडिया चौराहे पर एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली का पुतला फूंका। सुभाष रावत व मुकेश रावत के नेतृत्व में विरोध–प्रदर्शन के दौरान वक्ताओं ने कहा कि शौकत अली ने मुस्लिम

आक्रांता सैय्यद सलार मसूद गाजी का महिमामंडन करते हुए महाराजा सुहेलदेव को लुटेरा बताया है। इससे संपूर्ण पासी समाज में भारी आक्रोश है। नाराज लोगों ने महाराजा सुहेलदेव पासी पर अपमानजनक टिप्पणी करने वाले शौकत अली के खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलाने व उनकी गिरफ्तारी की मांग उठाई। इसको लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन भी सरोजनी नगर पुलिस को सौंपा। इस दौरान रंजीत सूरज रावत, बच्चू लाल पासी, राम किशोर पासी, राजेश रावत, सुबोध रावत, चांदनी रावत आदि मौजूद रहे।

कक्षाओं में घुसकर मारपीट और धमकाने का मामला, पूर्व प्रिंसिपल समेत 10 पर केस दर्ज

लखनऊ, (संवाददाता)। राजधानी लखनऊ में स्कूल में हुए हंगामे के बाद गुडंबा पुलिस ने पूर्व प्रिंसिपल सुप्रिया पांडेय समेत 10 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। एफआईआर में छात्र–छात्राओं के नाम भी शामिल हैं। डीजीएम आशुतोष कुमार ने पूर्व प्रिंसिपल और उनके साथियों पर स्कूल कर्मचारियों से मारपीट और गाली–गलौज करने का आरोप लगाया है। उनकी तहरीर के आधार पर केस दर्ज किया है। मामला जानकीपुरम स्थित नारायणा स्कूल का है। स्कूल के डीजीएम आशुतोष कुमार ने गुडंबा थाने में तहरीर दी। इसमें बताया कि पूर्व प्रिंसिपल सुप्रिया पांडेय को उनके व्यवहार के कारण प्रिंसिपल पद से हटा दिया गया था। बुधवार सुबह करीब 11 बजे वह अपने साथियों नीलिमा तिवारी, सुमित भौमिक, ओम, देव, पार्थ, सैवी पांडेय, इसिता, परसून वर्मा, काव्या चौधरी सहित कई अन्य बाहरी लोगों के साथ स्कूल पहुंची। यहां कक्षाओं में घुसकर कर्मचारियों से गाली–गलौज और मारपीट की। कर्मचारियों को जान से मारने की भी धमकी दी। इसके बाद घटना की सूचना पुलिस को दी गई। ममले में सुप्रिया पांडेय का कहना है कि उनके खिलाफ लगाए गए सभी आरोप बेबुनियाद हैं। स्कूल के बच्चों व अभिभावक पर वह स्कूल गई थीं। प्रबंधन ने बच्चों व अभिभावकों के साथ मारपीट की थी। स्कूल के सीसीटीवी कैमरों की जांच करके वास्तविकता की पड़ताल की जा सकती है। इंस्पेक्टर प्रभातेश कुमार श्रीवास्तव का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

महाभारतकालीन लाक्षागृह का एक करोड़ से होगा विकास

लखनऊ, (संवाददाता)। उत्तर प्रदेश में पर्यटन विभाग महाभारत सर्किट के अंतर्गत बागपत स्थित महाभारतकालीन स्थल लाक्षागृह का समेकित पर्यटन विकास करेगा। इसके लिए एक करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। बड़ौत के बरनावा गांव में हिंडन और कृष्णा नदी के संगम पर स्थित यह स्थल महाभारत काल का

ऐतिहासिक गवाह माना जाता है। पर्यटन व संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि विभाग लाक्षागृह जैसे महाभारतकालीन ऐतिहासिक स्थल को धार्मिक पर्यटन के मानचित्र पर प्रमुखता से स्थापित करेगा। यहां कौरवों ने पांडवों को जिंदा जलाने के लिए लाख का घर बनवाया था। उन्होंने कहा कि इस स्थल के संरक्षण और विकास से बागपत धार्मिक पर्यटन के मानचित्र पर और सशक्त होगा। उन्होंने बताया कि परियोजना के तहत यहां पर सौंदर्यीकरण, आधुनिक प्रकाश व्यवस्था, स्वच्छ शौचालय, सूचना केंद्र और पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। ताकि पर्यटक यहां पर आकर पूरा समय दे सकें। इस साल यहां पर 20 लाख से अधिक पर्यटक आने की संभावना है। उन्होंने कहा कि जिले में लाक्षागृह, पुरा महादेव, जैन धर्मावलंबियों का त्रिलोक तीर्थ धाम सहित कई पवित्र स्थल हैं। सरकार का प्रयास है कि इन स्थलों को विश्व पर्यटन गंतव्य को और अधिक सशक्त तरीके से स्थापित किया जाए, ताकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश की पहचान एक प्रमुख पर्यटन गंतव्य के रूप में और मजबूत हो सके।

संक्षिप्त खबरें

एमिटी विश्वविद्यालय में एग्रीफूड 2025 का भव्य शुभारंभ

लखनऊ, (संवाददाता)। एमिटी विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश, लखनऊ परिसर में आज "एग्रीफूड 2025रू कृषि एवं खाद्य विकास में प्रगति, सुधार और नवाचार" का भव्य शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री राकेश सचान ने किया। यह आयोजन एमिटी खाद्य एवं कृषि फाउंडेशन द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग (एक जनपद एक उत्पाद) के सहयोग से आयोजित किया गया।उद्घाटन अवसर पर मंत्री सचान ने कहा कि प्रदेश सरकार "एक जनपद एक उत्पाद" जैसी योजनाओं के माध्यम से कृषि और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में उद्यमिता एवं नवाचार को प्रोत्साहित कर रही है। उन्होंने बताया कि युवाओं को नवउद्यम (स्टार्टअप) और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम योजनाओं से जोड़कर आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। मंत्री ने एग्रीफूड 2025 जैसे आयोजनों को प्रदेश की कृषि और खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के लिए प्रेरणास्रोत बताया। उद्घाटन सत्र में एमिटी विश्वविद्यालय के संस्थापक अध्यक्ष प्रो. (डॉ.) अशोक के. चौहान और कुलपति प्रो. (डॉ.) बलविंदर शुक्ला ने अपने विचार साझा किए। प्रो. (डॉ.) अनिल वशिष्ठ, प्रो–उपकुलपति, ने उद्यमिता कौशल विकास की आवश्यकता पर विशेष बल दिया। इस दौरान संगोष्ठी की स्मारिका का भी विमोचन किया गया।तकनीकी सत्रों में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, आचार्य मनीष, उद्योग और शिक्षाविदों ने खाद्य सुरक्षा, आयुर्वेद की भूमिका, कृषि अपशिष्ट प्रबंधन, सुपरफूड जैसे मोरिंगा और सतत विकास जैसे विषयों पर अपने विचार रखे।संगोष्ठी का आयोजन निदेशक, एमिटी खाद्य एवं कृषि फाउंडेशन डॉ. शालिनी सिंह विसेन के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ।

उत्तर प्रदेश में लेखपाल डैशबोर्ड का शुभारंभ, राजस्व सेवाओं में डिजिटल पारदर्शिता बढ़ी

लखनऊ, (संवाददाता)। उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद के अध्यक्ष अनिल कुमार ने आज सरोजनी नगर तहसील में लेखपाल डैशबोर्ड का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि लेखपाल द्वारा किए जाने वाले सभी कार्य अब एक ही प्लेटफार्म पर दिखाई देंगे। सिंगल लॉगइन के माध्यम से कार्यों का सुचारू निस्तारण किया जा सकेगा और कार्यों की उच्च स्तर से सतत मॉनिटरिंग की जा सकेगी।अध्यक्ष ने बताया कि प्रदेश के 22,000 से अधिक लेखपाल प्रतिदिन नागरिकों के सबसे निकट रहकर भूमि अभिलेख अद्यतन, प्रमाणपत्र सत्यापन और अन्य राजस्व कार्यों का दायित्व निभाते हैं। अब "लेखपाल डैशबोर्ड" इन सभी कार्यों को ऑनलाइन और अधिक सुव्यवस्थित बनाएगा। इसके माध्यम से भूमि अभिलेख संशोधन, आय–जाति–निवास प्रमाणपत्रों की स्थिति, धारा 34, 80, 89 और 98 की कार्यवाहियाँ, हल्का मैपिंग और अवकाश स्वीकृति की प्रक्रियाएँ एकल लॉगिन पर उपलब्ध होंगी। उच्चाधिकारी अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के कार्यों की प्रगति और गुणवत्ता वास्तविक समय में देख सकेंगे।अध्यक्ष ने इस परियोजना को साकार करने में योगदान देने वाली एनआईसी की तकनीकी टीम, परिषद से सम्बद्ध सभी तहसीलदारों और लेखपालों की मेहनत की सराहना की। उन्होंने कहा कि यह पहल केवल तकनीकी विकास नहीं, बल्कि राजस्व परिवार के हजारों कर्मचारियों के सामूहिक प्रयास और महीनों की मेहनत का परिणाम है।

लखनऊ फॉल्कंस और टेक्ट्रो क्लब विजयी

लखनऊ, (संवाददाता)। लखनऊ फुटबॉल लीग का अंतिम चरण बृहस्पतिवार से इकाना फुटबॉल स्टेडियम में शुरू हुआ। पहले मुकाबले में जहां लखनऊ फॉल्कंस ने लखनऊ फॉल्कंस रिजर्व को 5–0 से करारी मात दी, जबकि दूसरे मुकाबले में टेक्ट्रो क्लब ने यूपी पुलिस को 2–0 से पराजित किया। लखनऊ फॉल्कंस और रिजर्व के बीच खेला गया मुकाबला पूरी तरह एकतरफा रहा, जिसमें लखनऊ फॉल्कंस के खिलाड़ियों ने दबदबा कायम किया। हालांकि पहले हाफ में कोई भी टीम गोल नहीं कर सकी। दूसरे हाफ के शुरू होते ही फॉल्कंस के खिलाड़ी हावी हो गए। टीम के स्टार खिलाड़ी शिवनाथ ने खेल के 53वें, 56वें और 64वें मिनट में गोल करते हुए अपनी हैट्रिक पूरी की। टीम से 74वें मिनट में यहेनाइज और 80वें मिनट में जसबरन ने गोल दागे। अंत में फॉल्कंस ने 5–0 से मुकाबला अपने नाम किया। दिन के दूसरे मुकाबले में टेक्ट्रो क्लब की भिड़ंत यूपी पुलिस से हुई। खेल के 13वें मिनट में उत्कर्ष ने साथी खिलाड़ी के पास पर गोल करते हुए टेक्ट्रो को 1–0 से बढ़त दिलाई। एक गोल से पिछड़ने के बाद यूपी पुलिस ने वापसी के लिए कई मूव बनाए, लेकिन टेक्ट्रो की सजग रक्षापंक्ति ने उनके सभी प्रयास व्यर्थ कर दिए। इस बीच खेल के 71वें मिनट में हिमांशु थापा ने गोल दागते हुए टेक्ट्रो की बढ़त को 2–0 तक पहुंचा दिया। यह गोल निर्णायक साबित हुआ। लीग में शुक्रवार को दिलकुशा ग्राउंड में लखनऊ सिटी क्लब बनाम स्पोर्ट्स कॉलेज और एक्स स्टूडेंट मेंस यूनाइटेड क्लब बनाम यूपी पुलिस के बीच मैच खेले जाएंगे। ला–मार्टीनियर लीग के तहत बृहस्पतिवार को खेले गए मुकाबलों में एएमसी और डाइमनोज क्लब ने जीत दर्ज की। ला–मार्टीनियर पोलो ग्राउंड में खेली जा रही प्रतियोगिता में पहला मुकाबला एएमसी और जेट्स क्लब बी के मध्य खेला गया। मुकाबला बेहद रोमांचक रहा, जिसमें एएमसी ने 2–1 से जीत हासिल करते हुए पूरे अंक प्राप्त किए। मैच के दौरान एएमसी के खिलाड़ियों ने बेहतर तालमेल का प्रदर्शन किया और मौकों को गोल में बदलते जीत हासिल की। विजेता टीम से नैनो और माठी ने एक–एक गोल किए, जबकि पराजित टीम से अंशुमान एक गोल करने में सफल रहे। दिन के दूसरे मुकाबले में डाइमनोज क्लब का सामना जेट्स क्लब ए से हुआ। यह मुकाबला भी बेहद संघर्षपूर्ण रहा, जिसमें बराबरी का खेल देखने को मिला। मैच का एकमात्र गोल खेल के 47वें मिनट डाइमनोज क्लब के ताहिर ने किया।

बागपत के लाक्षागृह का समेकित पर्यटन विकास, महाभारत सर्किट में नई पहल

लखनऊ, (संवाददाता)। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग ने महाभारत सर्किट के अंतर्गत बागपत जिले के बरनावा (वारणावत) गांव में स्थित महाभारतकालीन स्थल लाक्षागृह के समेकित पर्यटन विकास की महत्वाकांक्षी योजना को मंजूरी दी है। इस परियोजना के लिए 100 लाख रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई है।पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि लाक्षागृह महाभारत काल के महत्वपूर्ण स्थलों में से एक है, जहां कौरवों ने पांडवों को जिंदा जलाने के लिए लाख का घर बनवाया था। विभाग इस ऐतिहासिक स्थल को धार्मिक पर्यटन के मानचित्र पर प्रमुखता से स्थापित करने के प्रयास में है।मंत्री ने बताया कि परियोजना के तहत पर्यटन स्थल पर सौंदर्यीकरण, आधुनिक प्रकाश व्यवस्था, स्वच्छ शौचालय, सूचना केंद्र और पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इन सुविधाओं से न केवल स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि जनपद की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर को भी नई पहचान मिलेगी।बरनावा (वारणावत) लाक्षागृह बागपत जिला मुख्यालय से लगभग 35 किलोमीटर दूर स्थित है। मुख्य स्थल तक पहुंचने के लिए बागपत–मेरठ हाईवे के पास प्रवेश द्वार बनाया गया है। टीले पर सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) का बोर्ड नजर आता है। यह स्थल एएसआई के अधीन संरक्षित है।जयवीर सिंह ने बताया कि वर्ष 2024 में लाक्षागृह में 16,73,555 पर्यटक पहुंचे थे और साल के अंत तक यह आंकड़ा 20 लाख तक पहुंच सकता है। मेरठ और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के निकट होने के कारण पर्यटक आसानी से यहां पहुंच पा रहे हैं,।

समस्याएं दूर न होने पर किसानों ने दिया धरना

लखनऊ, (संवाददाता)। किसानों की समस्याओं का निराकरण न होने पर राष्ट्रीय किसान मजदूर यूनियन की ओर से बृहस्पतिवार को समेसी के सामुदायिक मिलन केंद्र पर धरना दिया गया। अधिकारियों के आश्वासन पर शाम पांच बजे किसानों ने धरना समाप्त किया। राष्ट्रीय किसान मजदूर यूनियन के मंडल महामंत्री हरिपाल वर्मा ने बताया कि लोकनिर्माण विभाग खंड 2 लखनऊ के सहायक अभियंता सूर्य मणि मिश्र धरना स्थल पर पहुंचे थे। उन्होंने समेसी कस्बे के बदहाल गलियारे में सीसी रोड बनवाने व कस्बा नगराम के पास गंगागंज–नगराम मार्ग के एक किमी हिस्से में अधूरी पड़ी सड़क को नवंबर माह में बनवाने का आश्वासन दिया। इसके अलावा हुसेनाबाद मार्ग पर उगी झाड़ियों की अविलंब सफाई कराने की जानकारी दी। महिला नायब तहसीलदार वसुंधरा धरना स्थल पर पहुंची, जहां किसानों से करीब दो घंटे वार्ता हुई। धरने पर बैठे किसान जमीन की पैमाइश, बंटवारा, बेदखली जैसी समस्याओं के निराकरण व सिरौना ड्रेन की सिल्ट सफाई के लिए मौके पर चकबंदी आयुक्त व सिंचाई विभाग के अधिशाषी अभियंता को मौके पर बुलाने पर अड़े रहे। मालूम को कि किसानों की विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए दो सप्ताह पहले जिम्मेदार अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा गया था। धरने में मुख्य रूप से मंडल उपाध्यक्ष राजेंद्र यादव, मंडल महामंत्री हरिपाल सिंह, जिला अध्यक्ष प्रमोद यादव, जिला महामंत्री रामसिंह, ब्लाक अध्यक्ष दिनेश कुमार, राकेश कुमार बब्लू, साहब दीन आदि संगठन के कार्यकर्ता धरने में शामिल रहे।

उत्तर प्रदेश में फार्मा और मेड–टेक क्षेत्र में सहयोग को नई दिशा

लखनऊ, । लाल बहादुर शास्त्री भवन (एनेक्सी) में चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश के नियंत्रणाधीन स्थापित संस्था प्रोमोट फार्मा काउंसिल और रायबरेली के बीच आपसी सहयोग को सुदृढ़ करने हेतु समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा विभाग पार्थ सारथी सेन शर्मा, मुख्यमंत्री के सलाहकार अवनीश अवस्थी, केवी राजू, डॉ. जीएन सिंह और छप्च्म्त् की निदेशक सुभिनी ए. सराफ सहित कई विशेषज्ञ उपस्थित रहे।प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा विभाग ने कहा कि इस एमओयू से प्रदेश को दवाओं और मेडिकल उपकरणों के निर्माण, अनुसंधान, नवाचार और कौशल विकास के क्षेत्र में ठोस लाभ प्राप्त होंगे। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार का उद्देश्य उत्तर प्रदेश को फार्मा, बायोटेक और मेड–टेक क्षेत्र में अग्रणी बनाना है।

शारदीय नवरात्रि पर महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा और स्वावलंबन के लिए मिशन-शक्ति अभियान

लखनऊ, (संवाददाता)। लखनऊ,। शारदीय नवरात्रि के अवसर पर महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन को सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश में विशेष अभियान मिशन–शक्ति संचालित किया जाएगा। इस अवसर पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों में महिला शक्ति की सहभागिता सुनिश्चित कराई जाएगी। नवरात्रि की शुभ तिथियां 22 सितंबर से 01 अक्टूबर 2025 तक हैं, जिसमें मां दुर्गा के नव स्वरूपों की विधिविधान पूजा की जाती है।पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि संस्कृति विभाग द्वारा इस वर्ष भी मिशन–शक्ति के अंतर्गत प्रदेश के देवी मंदिरों और शक्तिपीठों में महिलाओं और बालिकाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही, उनके सुरक्षा के लिए लागू कानूनों का व्यापक प्रचार–प्रसार करते हुए विशेष अभियान संचालित किया जाएगा। इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों और मण्डलायुक्तों को आवश्यक निर्देश 17 सितंबर को निर्गत कर दिए गए हैं।मंत्री ने बताया कि सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए चयनित प्रति मंडली एवं प्रति स्थल मानदेय के रूप में 5,000 रुपए की धनराशि तथा साउंड, लाइट, बैनर, बैकड्राफ, तख्त, दरी बिछावन, भोजन और प्रचार–प्रसार पर 5,000 रुपए की धनराशि व्यय की जाएगी। कलाकारों के मानदेय और अन्य व्यवस्थाओं हेतु प्रति जनपद 1 लाख रुपए उपलब्ध कराया जाएगा।मंदिरों में सामाजिक और राष्ट्रीय मूल्यों को जन सम्मान से जोड़ते हुए अखंड रामायण पाठ, सुंदरकाण्ड पाठ और दुर्गा सप्सती पाठ के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। प्रत्येक जनपद में जनपद स्तरीय, तहसील स्तरीय और विकासखण्ड स्तरीय समितियों का गठन कर कार्यक्रम संपन्न कराया जाएगा। जिलाधिकारियों के माध्यम से राम मंदिरों, हनुमान, वाल्मिकी और दुर्गा मंदिरों में लोक कलाकारों, भजन मंडलियों और कीर्तन मंडलियों का चयन कर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। जयवीर सिंह ने बताया कि इस वर्ष अष्टमी (30 सितंबर 2025) प्रातः 11:00 बजे से नवमी (01 अक्टूबर 2025) प्रातः 11रू00 बजे तक रामायण, सुंदरकांड और दुर्गा सप्सती का पाठ स्थानीय भजन मंडलियों और कीर्तन मंडलियों द्वारा संपादित कराया जाएगा। यह राज्य स्तरीय कार्यक्रम है, इसलिए सूचना एवं जनसंपर्क विभाग प्रिंट और सोशल मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार– प्रसार करेगा। कार्यक्रम स्थलों पर आवश्यक व्यवस्था जिला प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। मिशन–शक्ति के अंतर्गत प्रदेश के मंदिरों का चयन कर भावपूर्ण कार्यक्रम भव्य और गरिमामयी ढंग से सम्पन्न कराया जाएगा, जिससे महिलाओं और बालिकाओं की सहभागिता और सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

प्रार्थना पत्रों पर त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किया जाए - जिलाधिकारी

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर जिलाधिकारी डा0 दिनेश चन्द्र की अध्यक्षता तथा पुलिस अधीक्षक डा0 कौस्तुभ की उपस्थिति में तहसील सदर के प्रेक्षागृह में सम्पूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। सम्पूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर जिलाधिकारी के द्वारा गम्भीरतापूर्वक सुनवाई करते हुए सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि शिकायती प्रार्थना पत्रों पर त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किया जाए। सदर निवासी नन्हकू द्वारा जिलाधिकारी के समक्ष प्रार्थना–पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया कि उन्होंने अपने भाई का जमीन क्रय किया था तथा रजिस्ट्री हो जाने के पश्चात् भी अभी भी खतौनी में उनका भाई का नाम ही अंकित है जिस पर जिलाधिकारी ने तहसीलदार तत्काल आवश्यक

कार्यवाही करने के निर्देश दिये। जिलाधिकारी के समक्ष विरेन्द्र द्वारा अवगत कराया गया कि उनका पुस्तैनी मकान क्षत्रिग्रस्त होकर गिर गया है जिसके स्थान पर नया निर्माण कार्य हो रहा है किन्तु इसमें गतिरोध उत्पन्न किया जा रहा है, जिसपर जिलाधिकारी ने मौके पर जाकर निरीक्षण करते हुए गतिरोध को समाप्त कराने हेतु राजस्व और पुलिस की टीम को संयुक्त रुप से आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये। जिलाधिकारी के समक्ष राजेंद्र प्रसाद ने अवगत कराया कि उनकी जमीन का दाखिल खारिज हो चुका है रियल टाइम खतौनी का प्रिंट न मिलने के कारण गांव चकबंदी में चला गया जिसके कारण उनका नाम दर्ज नहीं हो पा रहा है जिस पर जिलाधिकारी ने उन्हें आश्वस्त कराया कि उनकी समस्या का आज ही समाधान कर दिया जाएगा, जिसके क्रम में आज ही तहसील दिवस के दौरान समस्या का निस्तारण करते हुए उन्हें खतौनी उपलब्ध करा दी गयी। इसी प्रकार जिलाधिकारी के समक्ष राजस्व विभाग, भूमि विवाद, पथरगड्डी, पेंशन आदि से सम्बन्धित शिकायती प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए जिसपर जिलाधिकारी ने सम्बन्धित विभाग के अधिकारियों को अग्रसारित करते हुए ससमय निस्तारण करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि अभियान चलाकर जितने भी पुराने वाद है उसका निस्तारण कराया जाए। जिलाधिकारी डॉ दिनेश चंद्र ने कहा कि मिशन शक्ति के पांचवें चरण का शुभारंभ हो गया है। इस दौरान रोस्टर के अनुसार पुलिस अधिकारी कर्मचारी गांव में जायेंगी। वहा पर पंचायत भवन में ग्राम पंचायत अधिकारी, एएनएम, आशा कार्यकर्ता आदि द्वारा महिला से सम्बन्धित योजनाओं पर चर्चा, परिचर्चा करेंगी। इस दौरान अच्छा कार्य करने वाली कर्मचारियों को सम्मानित किया जाएगा।

राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस 2025 के अवसर पर राष्ट्रीय फोटोग्राफी एवं कला प्रदर्शनी

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रशांत कुमार सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के आदेशानुसार समस्त नागरिकों को अवगत कराया है कि राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस 2025 के उपलक्ष्य में और न्याय तक पहुंच को बढ़ावा देने में नालसा की सेवा के तीन दशक पूरे होने पर, नालसा ''सभी के लिये न्यायः कानूनी सहायता के माध्यम से'' शीर्षक से एक राष्ट्रीय फोटोग्राफी और कला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर निम्नलिखित विषयवस्तु पर राष्ट्रीय फोटोग्राफी एवं कला प्रदर्शनी प्रस्तुत की जा सकती है। जिसमें महिला हक उसकी ताकत, समानता से सम्मान, नन्हें कदम बड़ा न्याय, बचपन सुरक्षित भविष्य सुरक्षित, बाधाओं से परे अधिकार हमारे, बुजुर्गी सहारा कानून का किनारा, स्वदेशी एवं अनुसूचित जनजातियां जंगल, जमीन और न्याय, निराशा और आशा के मध्य एक पुल, न्याय से आशा तक एक सफर, प्रवासी मजदूर, मजदूरी, आवास और समानता। घर से दूर हक है जरुर, पहचान है अधिकार और अधिकार से आधार, श्रमिक, किसान एवं मजदूर के कार्य गरिमा, मेहनत का मोल–न्याय का तोल, अपराध के पीड़ित और परिवार में न्याय के संग नये सबेरे की ओर, गाँव हो या शहर न्याय एक सहचर, सलाखों के भीतर न्याय की उम्मीद, बन्दियों के सम्मान, सुधार एवं दूसरा अवसर (बेड़ियों से बदलाव तक), लोक अदालत, संवाद से सुलह, संवाद से समाधान, सामुदायिक न्याय की भावना, अधिवक्ता, पराविधिक स्वयं सेवक और न्याय से आजीविका के लाभार्थी।

संक्षिप्त खबरें

जहरखुरानी की घटना को अंजाम देकर चोरी करने वाले दो आरोपी गिरफ्तार

अयोध्या। जहरखुरानी की घटना को अंजाम देकर चोरी करने वाले दो आरोपियों को थाना तारुन पुलिस ने गिरफ्तार किया।इस संबंध में शनिवार को पुलिस लाइन स्थित सभागार में आयोजित पत्रकार वार्ता में

जानकारी देते हुए एसपी ग्रामीण बलवंत चौधरी ने कहा गिरफ्तार किए गए यह आरोपी पहले दूर–दराज से आने वाले राहगीरों को जहर की पुरानी का शिकार बनाते थे और उसके बाद चोरी की वारदात करते थे। बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान मनोज राना पुत्र नेम सिह निवासी नार मोहम्मदपुर थाना जहागीर पुर जनपद गौतमबुद्ध नगर तथा मैनू उर्फ रामनरायन पुत्र सीताराम निवासी हतवा थाना नबाबगंज जनपद गोण्डा के रूप में हुई।थाना पुलिस ने इन आरोपियों को ऐमी घाट पुल से गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने वाली टीम में संदीप कुमार त्रिपाठी थानाध्यक्ष थाना तारुन,उ0नि0 रितेश सिह थाना तारून,उ0नि0 अरुण कुमार पटेल थाना तारून जनपद अयोध्या शामिल रहे।

राज्यमंत्री ने दिया चार चार लाख की आर्थिक मदद आकाशीय बिजली से मृतक तीन परिवारों को

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। खेल एवं युवा कल्याण राज्यमंत्री स्वतन्त्र प्रभार गिरीश चन्द्र यादव जी ने सदर विधानसभा क्षेत्र के शाहगंज तहसील के अतर्गत गयासपुर , नोनारी ग्राम के निवासी बहादुर पुत्र रामदास एवं सदर तहसील के अंतर्गत गोसाईपुर , सुल्तानपुर गौर ग्राम के निवासी किसन पुत्र लालमन और अतुल पुत्र बुद्धिराम का विगत दिनों आकाशीय बिजली से निधन हो गया था। खेल एवं युवा कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गिरीश चन्द्र यादव जी आकाशीय बिजली से मृतक इन तीनों के गांव पर जाकर शोक संतप्त परिजनों से भेंट कर संवेदनायें प्रकट किया। और आकाशीय बिजली से मृतक बहादुर की पत्नी लालती को , मृतक अतुल के पिता बुद्धिराम को एवं मृतक किसन की माता जैमुरता को राज्य आपदा मोचक निधि के अंतर्गत रु. 4,00,000/– (चार लाख) की आर्थिक सहायता का स्वीकृति प्रमाण पत्र दिया। इस अवसर पर उपजिलाधिकारी सदर सत्यवीर सिंह, जिला पंचायत सदस्य श्यामबाबू यादव , अजय सिंह, मनीष श्रीवास्तव, धर्मेंद्र मिश्रा सहित आदि लोग मौजूद रहे।

मिशन शक्ति फेज 5 के शुभारंभ के पहले सीओ सिटी व मिशन शक्ति कर्मियों ने सुनी सीएम योगी की बात

अयोध्या।।नवरात्रि में मिशन शक्ति फेज फाइव की शुरुआत होने से पहले कोतवाली नगर परिसर में सीओ सिटी शैलेंद्र सिंह के नेतृत्व में कोतवाली नगर पुलिस कर्मी व मिशन शक्ति की बीट पुलिस कर्मियों ने टीवी पर सीएम योगी आदित्य नाथ के विचारों को सुना।अपने संबोधन में योगी आदित्यनाथ ने विचारों को सुन रहे मिशन शक्ति बीट पुलिस कर्मियों से कहा कि समाज में मिशन शक्ति अभियान का किया जा रहा कार्य बहुत ही प्रशंसनीय है।मिशन शक्ति 5.0 की शुरुआत होने पर पहले चरण मे एक माह तक महिला पुलिस अधिकारी अपने ग्राम पंचायतों और शहरी वार्डों का दौरा करेंगी।उनके साथ ग्राम प्रधान, पार्षद, आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और स्वास्थ्य कर्मी भी होंगे।वे महिलाओं और स्कूली लड़कियों से सीधे बातचीत करेंगी,उनकी समस्याएँ सुनेंगी और सुरक्षा, अधिकारों और सरकारी कल्याणकारी कार्यक्रमों के बारे में जागरूकता बढ़ाएँगी। 22 सितंबर से प्रारंभ होने वाले नवरात्रि और आगे आने वाले त्योहारों पर विशेष व्यवस्था की जाएगी। दुर्गा पुजवा रामलीला के पंडालों के आसपास, मंदिरों, धार्मिक स्थलों, मेलों और भीड़–भाड़ वाले आयोजनों में मिशन शक्ति अभियान में तैनात महिला पुलिस कर्मी सादे व वर्दी में तैनात रहे।योगी आदित्यनाथ ने महिला उत्पीड़न से निपटने वाले एंटी–रोमियो स्क्वॉड को भी मजबूत करने का निर्देश दिया है।अभियान में उन्होंने केंद्र व राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को महिलाओं तथा अन्य ग्रामीणों को विस्तृत रूप से बताएं और उनको इसका लाभ लेने के लिए जागरूकता अभियान चलाये। मिशन शक्ति बीट में शामिल पुलिसकर्मी खासकर स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, अस्पतालों और उद्योगों में सेमिनार, चर्चाएँ और संवाद कार्यक्रम आयोजित किए जाएँगे।

स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा जारी

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय के लिए गर्व का क्षण है जब विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो. वंदना सिंह और रज्जू भैय्या संस्थान के रसायन विज्ञान विभाग के सहायक आचार्य डॉ. मिथिलेश यादव को स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा जारी विश्व के शीर्ष दो प्रतिशत प्रभावशाली पॉलीमर वैज्ञानिकों की सूची में पांचवीं बार शामिल किया गया है। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह सूची शोध गुणवत्ता, एच–इंडेक्स, साइटेशन और सह–लेखकों की संख्या जैसे वैज्ञानिक मानकों पर आधारित होती है।कुलपति ने पॉलीमर एवं बायोपॉलीमर नैनोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया है। विशेष रूप से पॉलिसैकेराइड आधारित नैनो पदार्थों के संश्लेषण, वर्णन और उनके व्यावहारिक अनुप्रयोगों में उनका शोध कार्य सराहनीय रहा है। उन्हें अब तक कई प्रतिष्ठित राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार व फैलोशिप प्राप्त हो चुके हैं। एडवांस्ड मटेरियल लेटेस्ट पत्रिका द्वारा उन्हें सर्वोच्च वैज्ञानिक सम्मान एएमएल मेडल भी प्रदान किया गया है। पूर्व में वह इलाहाबाद विश्वविद्यालय के रसायन विभाग की अध्यक्ष रह चुकी हैं। कुलपति पदभार ग्रहण करने के बाद से ही वह गुणवत्तायुक्त शोध को बढ़ावा देने के लिए सक्रिय प्रयास कर रही हैं। विश्वविद्यालय को भारत सरकार की पर्स योजना के अंतर्गत 7 करोड़ रुपये से अधिक का अनुदान प्राप्त हुआ है, जिसके लिए प्रस्तुतीकरण स्वयं कुलपति ने किया था। वहीं, रज्जू भैय्या संस्थान के सहायक आचार्य डॉ. मिथिलेश यादव को भी लगातार पांचवीं बार इस प्रतिष्ठित सूची में स्थान मिला है। पॉलीमर संश्लेषण एवं अनुप्रयोग के क्षेत्र में उन्हें 15 वर्षों से अधिक का शोध अनुभव है। उन्होंने अब तक 70 से अधिक अंतरराष्ट्रीय शोध पत्र प्रकाशित किए हैं, उनके नाम 3274 से अधिक गूगल साइटेशन हैं और उनका एच–इंडेक्स 29 है। वे "पॉलिमर" जर्नल के संपादक रह चुके हैं और वर्तमान में बायोपॉलीमर नैनोकम्पोजिट्स पर शोध कार्य कर रहे हैं। डॉ. यादव को विभिन्न संस्थाओं से कई शोध अनुदान प्राप्त हुए हैं। पूर्व में वे दक्षिण कोरिया और ताइवान में वरिष्ठ शोधकर्ता के रूप में कार्य कर चुके हैं और वर्ष 2014 से 2017 तक कोठारी पोस्ट–डॉक फेलो के रूप में जामिआ मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली में शोधरत रहे। इस उत्कृष्ट उपलब्धि पर कुलपति प्रो. वंदना सिंह एवं डॉ. मिथिलेश यादव को शनिवार को विश्वविद्यालय के कुलसचिव विनोद कुमार सिंह, उप कुलसचिव अमृत लाल, प्रो. मनोज मिश्र, प्रो. राजेश शर्मा, प्रो. प्रमोद कुमार यादव, प्रो. प्रदीप कुमार, डॉ. जान्हवी श्रीवास्तव, डॉ. आशीष वर्मा सहित विश्वविद्यालय के अन्य शिक्षकों ने बधाई दी है।

संक्षिप्त खबरें

खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन द्वारा गठित टीम कर रही छापेमारी

अयोध्या।आगामी नवरात्रिध्दशहरा पर्व पर लोगो को शुद्ध तथा ताजा खाद्य पदार्थ एवं पेय पदार्थ उपलब्ध कराये जाने हेतु सहायक आयुक्त (खाद्य)।।खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन मानिक चंद्र सिंह के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन द्वारा गठित टीम इस समय छापामार अभियान चला रही रहा है।शनिवार को इस अभियान में खाद्य सुरक्षा अधिकारी,अजय कुमार सोनी,जयदीप मौर्या, विवेक कुमार मौर्य,नन्द किशोर

यादव शामिल रहे।टीम मे शामिल कर्मियों ने संगम किराना स्टोर, कुमारगंज से 01 नमूना सेंधा नमक, 01 नमूना रिफाइण्ड मोमफली का तेल, दिनेश मिष्ठान भण्डार, कुमारगंज से 01 नमूना बर्फी का लिया।द्वितीय सचल दल मे शामिल खाद्य सुरक्षा अधिकारी संतोष कुमार साहू,अनूप सिंह, सुमित चौधरी, शरद पाल ने किराना स्टोर, भीखी का पुरवा से 01 नमूना घी, 01 नमूना सेंधा नमक, रिलायन्स स्मार्ट पाइन्ट से 01 नमूना फलाहारी नमकीन, 01 नमूना साबूदाना, 01 नमूना सेंधा नमक, 01 नमूना मिश्री का नमूना संग्रहित कर जांच हेतु प्रयोगशाला भेजा गया है।जिनकी जाँच रिपोर्ट प्राप्त होने पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जायेगी।

हरदोई में नवागत एसपी अशोक कुमार मीणा ने कार्यभार ग्रहण किया, रिजर्व पुलिस लाइंस में सलामी

हरदोई(अम्बरीष कुमार सक्सेना)। जिले में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने के उद्देश्य से नवागत पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा ने आज कार्यभार ग्रहण किया। इस अवसर पर रिजर्व पुलिस लाइंस में एक औपचारिक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें पुलिस अधिकारी एवं जवानों ने नवागत एसपी को सलामी देकर उनका

स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान एसपी मीणा ने पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने, अपराध नियंत्रण, और जनसुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनता के साथ पुलिस का विश्वास और सहयोग मजबूत करना प्राथमिकता होगी। नवागत एसपी ने यह भी कहा कि हरदोई में शांति और सुरक्षा बनाए रखना उनकी पहली जिम्मेदारी है। उन्होंने जवानों को कानून का पालन करते हुए ।

इनरव्हील क्लब द्वारा वेणी माधव बालिका इंटर कॉलेज में आयोजित की गई, आत्मरक्षा कार्यशाला

हरदोई(अम्बरीष कुमार सक्सेना) इनरव्हील क्लब हरदोई डी ओ डी के तत्वावधान में वेणी माधव बालिका इंटर कॉलेज में आत्मरक्षा कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रशिक्षक आशुतोष अस्थाना एवं आकाश अस्थाना ने छात्राओं को आत्मरक्षा की विभिन्न तकनीकें सिखाईं। बालिकाओं ने प्रायोगिक अभ्यास कर आत्मरक्षा के गुरों को सीखा और अपनी जिज्ञासाओं का समाधान भी प्राप्त किया। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य छात्राओं में आत्मसुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना और उनमें आत्मविश्वास का विकास करना रहा। क्लब अध्यक्ष पारुल तिवारी ने कहा कि आत्मरक्षा का ज्ञान प्रत्येक बालिका के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यह उन्हें हर परिस्थिति में सक्षम और सशक्त बनाता है। उन्होंने दोनों प्रशिक्षकों का आभार व्यक्त करते हुए छात्राओं को नियमित अभ्यास करने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में समाजसेविका कुमुदिनी देवी, कॉलेज की प्रधानाचार्या गीता द्विवेदी, उप प्रधानाचार्या पूनम सक्सेना, क्लब आईएसओ सोहिनी दीक्षित, सीसीपीसी रागिनी तिवारी, विभा सिंह तथा एवीएन की शारीरिक शिक्षा की शिक्षिका मैना गुप्ता उपस्थित रहीं। सभी ने कार्यशाला की सराहना करते हुए इसे समय की आवश्यकता बताया। अंत में क्लब अध्यक्ष पारुल तिवारी ने विद्यालय प्रशासन एवं उपस्थित अतिथियों का आभार व्यक्त किया।

मिशन शक्ति–5.0 का शुभारंभ, उच्च शिक्षा राज्यमंत्री रजनी तिवारी ने की सहभागिता

हरदोई(अम्बरीष कुमार सक्सेना) कलेक्ट्रेट परिसर में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा नारी सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन को समर्पित "मिशन शक्तिदृ5.0" के शुभारंभ कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस अवसर पर राज्यमंत्री रजनी तिवारी ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी के मार्गदर्शन में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा, सशक्तिकरण एवं सम्मान के उद्देश्य से "मिशन शक्ति" अभियान का पहला चरण 17 अक्टूबर 2020 को शुरू किया गया था। अब तक इसके चार चरण सफलतापूर्वक पूरे किए जा चुके हैं और पांचवां चरण 3 अक्टूबर 2024 से प्रारंभ हुआ है। उन्होंने बताया कि इस अभियान में महिला

एवं बाल विकास विभाग के साथ–साथ गृह विभाग, 28 अन्य विभागों, समाजसेवी संस्थाओं और शैक्षणिक संस्थानों ने सक्रिय सहभागिता की है। पहले चार चरणों में विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से प्रदेशभर में 9 करोड़ से अधिक लोगों तक पहुँच बनाकर उन्हें सरकार की योजनाओं एवं कार्यक्रमों की जानकारी दी गई। इस अवसर पर उच्च शिक्षा राज्यमंत्री रजनी तिवारी ने सहभागिता की तथा अंतर्राष्ट्रीय पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी रुचि त्रिवेदी को सम्मानित किया। कार्यक्रम में जिलाधिकारी अनुनय झा, पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा एवं मुख्य विकास अधिकारी सान्या छाबड़ा उपस्थित रहीं।

युवा मरीज में 8 सेंटीमीटर के रेयर एओर्टिक टियर का मैक्स अस्पताल, लखनऊ, में 'फ्रोजन एलीफेंट ट्रंक' सर्जरी से हुआ सफल इलाज

लखनऊ (प्रत्यूष पाण्डेय).मैक्स सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, लखनऊ, के डॉक्टरों ने प्रयागराज के 27 वर्षीय युवक पर "फ्रोजन एलीफेंट ट्रंक" प्रोसिजर का इस्तेमाल कर एक असाधारण और जटिल सर्जरी करी, जिसमे एसेन्डिंग एओर्टा और एओर्टिक आर्च का रिप्लेसमेंट, ब्रेन आर्टरी की डिब्रांचिंग की गई और डिसेन्डिंग थोरेसिक एओर्टा के लिए एओर्टिक–स्टेंटेड हाइब्रिड ग्राफ्ट लगाया गया। मरीज में लगभग 8 सेंटीमीटर की बड़ी एओर्टिक डिसेक्शन पाई गई थी, जो एओर्टिक रूट से लेकर एब्डॉमिनल एओर्टा तक फैली हुई थी। यदि इलाज न होता तो यह किसी भी समय फट सकती थी और तुरंत मृत्यु हो सकती थी। डॉ. विजयंत देवेघ्नराज, डायरेक्टर और हेड ऑफ डिपार्टमेंट, कार्डियोथोरेसिक एवं वैस्कुलर सर्जरी (सीटीवीएस), मैक्स सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, लखनऊ, के नेतृत्व में डॉक्टरों की टीम ने लगभग 7 घंटे चली इस मैराथन सर्जरी को अंजाम दिया। इसमें पूरे शरीर – दिल, दिमाग, किडनी, लिवर आदि का ब्लड सर्कुलेशन रोकना पड़ा। इस दौरान मरीज के शरीर का तापमान "डीप हाइपोथर्मिक टोटल सर्क्युलेटरी अरेस्ट" (डीएचसीए) के जरिए 18 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया गया और फिर सर्जरी की गई। मरीज आलोक, को लगभग पाँच महीने से सीने में दर्द और सांस फूलने की समस्या थी, जिसे उन्होंने ऐसिडिटी या सीने में जकड़न समझकर नजरअंदाज कर दिया। स्थिति बिगड़ने पर परिवार ने उन्हें मैक्स अस्पताल में दिखाया, जहाँ जांच और सीटी एओर्टोग्राम से यह

खतरनाक एओर्टिक डिसेक्शन की कंडीशन सामने आई। डॉक्टरों ने यह भी आशंका जताई कि उन्हें मार्फन सिंड्रोम हो सकता है दृ यह एक जन्मजात कनेक्टिव टिशू डिसॉर्डर है, जिससे ऐसी वैसकुलर समस्या हो सकती हैं। मामले की जानकारी देते हुए डॉ. विजयंत देवेघ्नराज, ने कहा, "मरीज आलोक को महीनों से लक्षण थे, लेकिन उन्होंने इसे गैस या सीने की जकड़न समझा। जब सीने का तेज दर्द और सांस की गंभीर समस्या लगातार बनी रही, तो परिवार के लोग उन्हें विशेषज्ञ देखभाल के लिए मैक्स लेकर आए। उनकी कम उम्र के कारण यह एक असाधारण और कठिन मामला था। उनकी एओर्टिक रूट से लेकर एब्डॉमिनल एओर्टा तक एक 8 सेमी का डिसेक्शन पाया गया जो गुर्दे की धमनियों से ठीक पहले था, साथ ही दिमाग, सीने और पेट के मुख्य अंगों को खून पहुंचाने वाली आर्टरीज को प्रभावित कर रहा था। हमने एक असामान्य और जटिल हाइब्रिड सर्जरी 'फ्रोजन एलीफेंट ट्रंक' करने का तय किया। ये नाम इसके शेप की वजह से मिला है। इस सर्जरी में हमने ऐऑर्टा के जिस हिस्से में नुकसान पहुंचा था उसे रिप्लेस किया, एसेन्डिंग एओर्टा और एओर्टिक आर्च और ब्रेन आर्टरीज का पूरा रिप्लेसमेंट,और डिसेन्डिंग थोरेसिक एओर्टा में एओर्टिक–स्टेंटेड हाइब्रिड ग्राफ्ट लगाया और ये सब एक ही ऑपरेशन में किया गया।" सर्जरी के बारे में आगे बताते हुए डॉ. देवेघ्नराज, ने कहा, "दिल और मुख्य आर्टरीज पर सुरक्षित काम के लिए मरीज के शरीर को लगभग 18 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया गया और लगभग 35दृ40 मिनट तक पूरे शरीर का ब्लड सर्कुलेशन रोका गया।

प्रांतीय कार्यकारी की बैठक संपन्न

अयोध्या। उत्तर प्रदेश पूर्वी परिमंडल भारत संचार निगम लिमिटेड एम्पलाई यूनियन की प्रांतीय कार्यकारी की बैठक कामरेड आनंद कुमार सिंह के नेतृत्व में हुई।इस मौके पर मुख्य अतीत के रूप में अभिषेक मित्र महासचिव नई दिल्ली मौजूद रहे।उनके अलावा कामरेड त्रिभुवन नारायण तिवारी,कामरेड रमाशंकर तथा विभिन्न जिलों से आए जिला सचिव संगठन सचिव सहायक जिला सचिव ने भाग लिया और उन सभी ने मुख्य अतिथि के सामने अपने जिलों की समस्याओं को रखा।

सान्ध्य हिन्दी दैनिक देश की उपासना

स्वात्वाधिकारी में. प्रभुदयाल प्रकाशन की ओर से श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव मुद्रक, प्रकाशक एवं सम्पादक द्वारा देश की उपासना प्रेस, उपासना भवन, धर्मसारी, प्रेमापुर, जौनपुर उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं प्रकाशित।

सम्पादक
श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव
मो0 - 7007415808, 9415034002
Email - deshkiupasanadailynews@gmail.com

समाचार–पत्र से संबधित समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र जौनपुर न्यायालय होगा।